वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में बजट पेश किया। इसमें हर क्षेत्र को किसी न किसी तरह से राहत देने की कोशिशें की गई हैं। स्पष्ट कर दिया है कि एमएसपी जारी रहेगी।

जनहितैषी

हिन्दी दैनिक

R.N.I. No. 63177/95 वर्ष:27 अंक: 51 दिनांक: 02-02-2022 बुधवार मूल्य : 100 पैसा पृष्ठ:4 अहमदाबाद M

मंगलवार को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 810वें उर्स पर अजमेर शरीफ दरगाह पर कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से चादर भेंट करते राहुल गांधी और अन्य नेता।

जारी रहेगी एमएसपी; बजट में अनाज की सरकारी खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ का बंदोबस्त

नई दिल्ली। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खाद्यान्न की होने वाली सरकारी खरीद को लेकर उठते सवालों पर विराम लगाते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट कर दिया है कि एमएसपी जारी रहेगी। बजट प्रस्तावों में पहली बार सरकारी खरीद को शामिल किया गया है।

वित्तमंत्री ने बजट भाषण में कृषि क्षेत्र पर अपनी बात की शुरुआत ही अनाज की सरकारी खरीद से की। उन्होंने कहा कि रबी सीजन 2021-22 और खरीफ सीजन में कुल 12.08 करोड़ टन गेहूं व धान की खरीद की जाएगी। इसका लाभ 1.63 करोड़ किसानों को मिलेगा। गेहूं व धान की खरीद पर कुल 2.37 लाख करोड़ रुपए व्यय होंगे। इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में किया जाएगा। हालांकि, बजट में दूसरी फसलों का उत्पादन करने वाले किसानों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

एमएसपी को लेकर किसानों के बीच भ्रम फैल रहा था कि सरकार इसे बंद कर सकती है जिसे बजट के मार्फत साफ कर दिया गया है। दरअसल, राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी इस घोषणा के मायने निकाले जा सकते हैं। परंतु, सरकार के समक्ष खाद्यान्न की खरीद करना उसकी बड़ी जिम्मेदारी भी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के तहत देश की दो तिहाई आबादी को राशन प्रणाली के तहत अति रियायती दर पर अनाज वितरण करना ही है। इसके लिए कुल छह करोड़ टन से अधिक अनाज की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी खाद्यान्न की जरूरत पड़ती है। इसलिए सरकार के लिए अनाज की खरीद करना उसकी मजबूरी भी है।

केंद्र ने केंद्रीय बजट 2022-23 में ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ रुपये आवंटित किए। यह मौजूदा वित्त वर्ष के लिये संशोधित आकलन से 25.51 प्रतिशत कम है। निर्मला सीतारमण ने पिछले साल के बजट में भी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (मनरेगा) के लिए 73,000 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। हालांकि, बाद में काम की अधिक मांग के कारण इस संशोधित कर 98,000 करोड़ रुपये कर दिया गया था।

मनरेगा का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक वित्तीय वर्ष में हर परिवार के लिये कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान करना है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से तैयार हों। पहले चरण में यह योजना दो फरवरी 2006 से 200 सबसे पिछड़े जिलों में लागू की गई थी, बाद में इसे एक अप्रैल, 2007 से 113 और 15 मई 2007 से 17 अतिरिक्त जिलों तक बढ़ा दिया गया था। शेष जिलों को एक अप्रैल, 2008 से अधिनियम के तहत शामिल किया गया था। अधिनियम में अब देश के सभी ग्रामीण जिले शामिल हैं।

कोयले की अवैध खदान हादसे में 13 लोगों की मौत

- कई लोगों के दबे होने की आशंका

धनबाद (ईएमएस)। धनबाद के निरसा क्षेत्र में कोयले के अवैध खनन हादसे में 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं, दर्जनों लोगों के अंदर फंसे होने की भी आशंका हैघ मामले की जांच करने के लिए पुलिसबल मौके पर मौजूद है।

धनबाद जिले में इन दिनों अवैध कोयला कारोबार का सेंटर बना हुआ है। निरसा थाना क्षेत्र के गोपिनाथपुर ओसीपी में अवैध कोयला उत्खनन स्थल में चॉल धसने से 13 मजदूर की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इस घटना में कई मजदूर गम्भीर रूप से घायल भी हुए हैं। अवैध कोयला उत्खनन स्थल में जेसीबी के जरिए मजदूरों को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि पानी भरे होने के कारण बचाव कार्य के दौरान कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसर हर दिन की तरह भारी संख्या में महिला, पुरुष कई समेत बच्चे अवैध उत्खनन करने के लिए आउटसोर्सिंग पर आए हुए थे। वहां ईसीएल प्रबंधन की ओर से ट्रेंच कटिंग किया गया था। इसी दौरान अचानक यह हादसा हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद धनबाद के निरसा पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली।

धनबाद जिले निरसा थाना क्षेत्र के गोपिनाथपुर ओसीपी में अवैध कोयला उत्खनन स्थल में चॉल धसने से 13 मजदूर की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इस घटना में कई मजदूर गम्भीर रूप से घायल भी हुए हैं। अवैध कोयला उत्खनन स्थल में जेसीबी के जरिए मजदूरों को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि पानी भरे होने के कारण बचाव कार्य के दौरान कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है।

आम बजट को विपक्षी नेताओं ने गीला पटाखा जैसा बताया

नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश आम बजट पर सत्ता और विपक्ष के बीच घमासान शुरू हो गया है। विपक्ष ने आम बजट के लिए मोदी सरकार को आड़े हाथ लेकर कहा कि मोदी सरकार ने देश के वेतनभोगी वर्ग और मध्यम वर्ग को राहत नहीं देकर उनके साथ विश्वासघात' और युवाओं की जीविका पर आपराधिक प्रहार किया है।कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बजट पर पहला रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि यह बजट गीला पटाखा जैसा है।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मोदी सरकार के बजट में कुछ नहीं है। मध्यम वर्ग, वेतनभोगी वर्ग, गरीब और वंचित वर्ग, युवाओं, किसानों और एमएसएमई के लिए कुछ नहीं है।'' वहीं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया,भारत का वेतनभोगी वर्ग एवं मध्यम वर्ग महामारी, वेतन में चौतरफा कटौती और कमरतोड़ महंगाई के दौर में राहत की उम्मीद कर रहा था।लेकिन वित्तमंत्री और प्रधानमंत्री ने फिर से अपने प्रत्यक्ष कर से संबंधित कदमों से इन वर्गों को बहुत निराश किया है।उन्होंने आरोप लगाया कि यह वेतनभोगी वर्ग और मध्यम वर्ग के साथ विश्वासघात है।इसके साथ ही सुरजेवाला ने सवाल किया कि क्या सरकार ने 'क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय पर कर लगाकर 'क्रिप्टो करेंसी' को बिना विधेयक लाए ही वैध करार दिया है?

माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने ट्वीट किया, बजट किसके लिए है? सबसे अमीर 10 प्रतिशत भारतीय देश की कुल संपत्ति के 75 प्रतिशत के स्वामी हैं। नीचे के 60 प्रतिशत लोग सिर्फ पांच प्रतिशत संपत्ति के मालिक हैं।महामारी के दौरान अधिक मुनाफा कमाने वालों पर अधिक कर क्यों नहीं लगाया गया?'' उन्होंने दावा किया, ''शहरी रोजगार गारंटी के बारे में कोई घोषणा नहीं।मनरेगा के लिए आवंटन पिछले साल के बराबर 73 हजार करोड़ रुपये रहा। युवाओं की जीविका पर आपराधिक हमला हुआ है।''

तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, ''बेरोजगारी और महंगाई से पिस रहे आम लोगों के लिए बजट में कुछ नहीं है। ममता के अलावा तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डेरेक ओब्रायन ने दावा किया कि बजट से साबित होता है, कि प्रधानमंत्री मोदी किसानों, गरीबों और मध्य वर्ग की परवाह नहीं करते। उन्होंने ट्वीट किया,हीरे सरकार के सबसे अच्छे मित्र हैं। किसानों, मध्य वर्ग, दिहाड़ी मजदूरों, बेरोजगारों की प्रधानमंत्री कोई परवाह नहीं करते।

शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि क्रिप्टो सहित विश्व करेंसी पर जो टैक्स लगाने की बात कही है, वह एक अच्छा कदम है, क्योंकि इसके जरिए डिजिटल करेंसी को रेगुलेट किया जा सकेगा।

इसी कड़ी में बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि करों की मार से कराह रही जनता को नये वादों से लुभाने का प्रयास बजट में हुआ है, जबकि बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई पर रोकथाम के कोई उपाय नहीं किए है।मायावती ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा, संसद में पेश आम बजट नए वादों के साथ जनता को लुभाने के लिए लाया गया है, जबकि गतवर्षों के वादों व पुरानी घोषणाओं आदि के अमल को भुला दिया गया है, यह कितना उचित। केन्द्र बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व किसानों की आत्महत्या जैसी गंभीर चिन्ताओं से मुक्त क्यों।

देशभर के छात्रों के लिए स्थापित की जाएगी डिजिटल यूनिवर्सिटी

नई दिल्ली (ईएमएस)। आम बजट पेश करते हुए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतीरमण ने कहा कि भारत सरकार ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए विश्व स्तरीय डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित करेगी। दरअसल बीते 2 वर्षो के दौरान कोरोना महामारी के कारण छात्रों एवं शैक्षणिक जगत को सबसे अधिक नुकसान झेलना पड़ा है। जहां एक और स्कूल कॉलेज बंद रहे वहीं ऑनलाइन पढ़ाई के लिए भी पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं थे। अब केंद्र सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा को सुऑढ़ता प्रदान करने के लिए बाकायदा एक डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित करने का बजट प्रावधान किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात कही। उन्होंने बताया यह डिजिटल विश्वविद्यालय देशभर के सभी छात्रों के लिए उपलब्ध होगा। यह एक बहुभाषी विश्वविद्यालय होगा जिसका लाभ भारत के सभी क्षेत्रों में रहने वाले छात्र ले सकेंगे।

वित्त मंत्री के मुताबिक भारत का यह डिजिटल विश्वविद्यालय उच्चतम एवं बेहतरीन टेक्नोलॉजी से युक्त होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि डिजिटल विश्वविद्यालय से देश के कई विख्यात विश्वविद्यालयों को जोड़ा जाएगा। अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल कर चुके देश के नामी विश्वविद्यालय इस डिजिटल विश्वविद्यालय की मदद करेंगे। देश के अलग-अलग विश्वविद्यालयों की सहायता से यहां पाठयक्रमों को बनाया और लागू किया जाएगा। साथ ही फेकल्टी और छात्रों को भी इस अनुभव का लाभ प्राप्त होगा।

गौरतलब है कि स्वयं शिक्षा मंत्रालय बीते 2 वर्ष के दौरान शिक्षा के डिजिटल माध्यमों को सशक्त बनाने का प्रयास करता रहा है। छात्रों के लिए ऑनलाइन पाठय सामग्री उपलब्ध कराने वाले शिक्षा मंत्रालय के पोर्टल 'दीक्षा' को प्रतिदिन 5 करोड़ से अधिक हिट मिल रहे हैं। यही कारण है कि शिक्षा मंत्रालय सभी राज्यों में स्कूली शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-कंटेंट उपलब्ध कराने के लिए 'नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्च र' को मजबूत कर रहा। इसके साथ ही सभी ग्रेड के लिए विशेष क्यूआर कोडेड एनर्जाइज्ड टेक्स्टबुक, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार की गई हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार की गई यह डिजिटल पाठय सामग्री दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध है।

शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक अब तक दीक्षा में 402 करोड़ से अधिक शिक्षण सत्र, 4,844 करोड़ से अधिक सीखने के मिनट और 5 करोड़ से अधिक औसत दैनिक पृष्ठ हिट के साथ 2,730 करोड़ से अधिक पृष्ठ हिट हैं। मंत्रालय का कहना है कि आज की तारीख में दीक्षा पर कुल 2,27,704 ई-कंटेंट लाइव हैं। वहीं वर्ष 2022 -23 के बजट में ऑनलाइन शिक्षा को और अधिक मजबूती देने के प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत जहां डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है वहीं स्कूली छात्रों के लिए भी कई प्रावधान किए गए हैं जिनमें डीटीएच आधारित टीवी चैनल्स की संख्या बढ़ाना शामिल है।

बुनियादी ढांचे, अधिक निवेश, और अधिक नौकरियों की नई संभावनाओं से भरा बजट

नई दिल्ली (ईएमएस)।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को लोगों के अनुकूल और प्रगतिशील बताकर कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत वित्तीय दस्तावेज अधिक बुनियादी ढांचे, अधिक निवेश, अधिक विकास और अधिक नौकरियों की नई संभावनाओं से भरा है। उन्होंने कहा, भारत के कोटि-कोटि जनों की आस्था, मां गंगा की सफाई के साथ-साथ किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन पांच राज्यों में गंगा किनारे, नैचुरल फॉर्मिंग को प्रोत्साहन देने का काम बजट में किया गया है।

पीएम मोदी ने कहा, यह बजट 100 साल की भयानक आपदा (कोविड-19) के बीच विकास का एक नया विश्वास लेकर आया है। यह बजट अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ आम आदमी के लिए कई नए अवसर पैदा करेगा।पीएम मोदी ने कहा कि इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू गरीबों का कल्याण है। हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से पानी हो, शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इसपर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी जोर दिया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आम लोगों की प्रतिक्रियाओं ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को उनकी सेवा करने का एक नया संकल्प दिया है।पीएम मोदी ने कहा कि देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट जैसे इलाकों के लिए पर्वतमाला योजना शुरू हो रही है।यह योजना पहाड़ों पर परिवहन की एक आधुनिक प्रणाली का निर्माण करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे कल बजट पर विस्तार से चर्चा करने वाले है। उन्होंने कहा, भाजपा ने मुझे बुधवार की सुबह 11 बजे बजट और आत्मनिर्भर भारत विषय पर बोलने के लिए आमंत्रित किया है। कल बजट पर विस्तार से बोलूंगा।

मालदीव में इंडिया आउट का नारा लगाने पर 6 माह की जेल और भारी जुर्माना लगेगा

नई दिल्ली (ईएमएस)। भारत और मालदीव में हमेशा के अच्छे पड़ोसी रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से चीन की बढ़ती गतिविधियों के कारण मालदीव रणनीतिक रूप से भारत से दूर हो रहा है।हाल ही में सोशल मीडिया पर मालदीव से कई वीडियो सामने आईं, जिसमें लोग 'इंडिया आउट की टी-शर्ट पहने भारत सरकार का विरोध जताते नजर आ रहे हैं।इसके बाद में इस तरह के प्रदर्शनों को रोकने के लिए सत्ताधारी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) ने बड़ा कदम उठाया है।

मालदीव में चीन समर्थक पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की तरफ से भारत के खिलाफ चल रहे' इंडिया आउट अभियान को मालदीव सरकार अवैध घोषित करने के लिए नया विधेयक लेकर आ रही है।19 दिसबंर को विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया था, कि भारत के खिलाफ फैलाए जा रहे झूठ और नफरत को लेकर मालदीव सरकार चिंतित है।भारत हमारा सबसे करीबी द्विपक्षीय साझेदार है, लेकिन कुछ समूह और नेता संबंधों को खराब करने के लिए प्रॉपेगैंडा फैला रहे हैं।

नए विधेयक में भारत विरोधी नारे लगाने वालों से 20,000 मालदीवियन रुफिया का जुर्माना वसूला जाएगा, इसके साथ ही 6 महीने की जेल या फिर 1 साल के लिए नजरबंद किया जा सकता है।मालदीव के स्थानीय पत्रकार ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, मालदीव सरकार ने इंडिया आउट नारे के प्रयोग को अपराध घोषित करने का फैसला किया है, सत्ताधारी पार्टी द्वारा तैयार किए गए विधेयक के मुताबिक, इस अभियान में हिस्सा लेने वालों को 6 माह तक की जेल होगी है। मालदीव के लोग वहां मौजूद भारतीय सैनिकों और उपकरणों को अपने देश से निकालने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी।ऐसा पहली बार नहीं है, जब मालदीव में भारतीय सेना और भारत सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए हैं। ऐसा ही विरोध साल 2012 में हुआ था,इसके बाद भारतीय एयरपोर्ट ऑपरेटर जीएमआर को उस साल मालदीव छोड़ भारत लौटना पड़ा था।

विकास फाटक उर्फ हिन्दुस्तानी भाऊ और इकरार खान को 4 फरवरी तक पुलिस हिरासत में

मुंबई (ईएमएस)। विकास फाटक उर्फ हिन्दुस्तानी भाऊ और इकरार खान को अदालत ने 4 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। उस पर धारावी में छात्रों को आंदोलन करने के लिए उकसाने का आरोपहै। हालांकि विकास फाटक ने जो भी हुआ उसके लिए बिना शर्त माफी भी मांगी और नुकसान भरपाई करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन पुलिस ने मामले में फंडिंग की जांच के लिए पुलिस हिरासत की मांग की, जिसे अदालत ने मान लिया।

जानकारी के मुताबिक धारावी पुलिस अब आरोपी से ये जानने की कोशिश में है कि धारावी में अचानक से इतने छात्र कैसे पहुंचे। छात्रों को भड़काने वाला आरोपी हिन्दुस्तानी भाऊ पांच सितारा होटल में किसके पैसे से ठहरा था। कहीं इस सबके पीछे कोई संगठन तो नहीं। पुलिस अब इन सब सवालों का जवाब जानना चाहती है। डीसीपी जोन 5 प्रणय अशोक ने बताया कि इनके साथ में और कौन थे, इनके पीछे अगर और कोई है तो उसका पता लगाया जाएगा। साथ ही इन्होंने कैसे सोशल मीडिया को यूज किया है, इन सबकी जांच करना जरूरी है।

वकील बचान पक्ष महेश मुले ने बताया कि निवेदन देने के लिए बुलाया था, दंगल करने के लिए नही बुलाया था। ना ही ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा है। भाऊ ने कोर्ट में भी बोला कि डेढ़ साल से उनको निवेदन दे रहा हूं, कुछ नही हो रहा है। छात्र पीछे पड़े थे इसलिए मैं गया था। सोशल मीडिया में भी यही सब लिखा था।

बजट से आसान होगी यूपी चुनाव में बीजेपी की राह किसानों के लिए कई बड़े ऐलान

नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री की ओर से खेती और किसानों के लिए किए गए बड़े ऐलानों को यूपी चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर एक साल तक चले आंदोलन की वजह से किसानों की नाराजगी को दूर करने का प्रयास करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अगले वित्त वर्ष में किसानों के खाते में 2.37 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से दिए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि गंगा नदी के किनारे जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। गंगा नदी के पांच किमी चौड़े कोरिडोर्स की कृषि भूमि पर पहले चरण में विशेष ध्यान दिया जाएगा। इतना ही नहीं उन्होंने किसानों के लिए कुछ अन्य ऐलान भी किए। दरअसल, अपने बजट भाषण में सीतारमण ने कहा कि एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीददारी की जाएगी हुए साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया जाएगा। तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में भी सरकार काम करेगी। ऑर्गेनिक खेती पर सरकार का जोर रहगा, किसानों को डिजिटल सर्विस मिलेगी। इसके अलावा सिंचाई, पेयजल सुविधाएं बढ़ाने पर भी जोर रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि 'हेंज;गंगा नदी के किनारे पांच किमी चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। रेलवे छोटे किसानों और उद्यमों के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स विकसित करेगा। स्थानीय उत्पाद की सप्लाई चैन बढ़ाने के लिए 'एक स्टेशन, एक उत्पाद' योजना शुरू की जाएगी। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए पीपीपी मोड में योजना शुरू की जाएगी।

किसानों के समावेशी विकास को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में 1000 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जाएगी, जिससे 1 करोड़ से अधिक किसानों को फायदा होगा। खेती-किसानी में टेक्नॉली के इस्तेमाल के लिए 'किसान ड्रोन' की घोषणा की गई है। इसके तहत फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड, कीटनाशकों के छिड़काव आदि के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए भुगतान करेगी। साल 2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। तिलहन उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए योजना लाई जाएगी। किसानों को ध्यान में रखकर किए गए ऐलानों को यूपी चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड, यूपी सहित पांच राज्यों में किसानों की नाराजगी दूर करने का प्रयास किया गया है। हालांकि, किसान बजट से कितना खुश हैं यह तो 10 मार्च को चुनावी नतीजे ही बताएंगे।

बजट से पहले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 91.50 रुपए कम हुए

नई दिल्ली (ईएमएस)। संसद में बजट प्रस्तुत किए जाने से ठीक पहले होटल, रेस्त्रा कारोबारी के लिए गुड न्यूज आ गई है। मंगलवार को तेल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की है। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 91.50 रुपए की तगड़ी कटौती की है। इस कटौती के साथ ही अब कमर्शियल गैस सिलेंडर दिल्ली में 1907 रुपए का हो गया है। नए साल की शुरुआत में ही तेल कंपनियों ने 19 किलो के गैस सिलेंडर की कीमत में 102.50 रुपये की कटौती की थी, लेकिन सिलेंडर की कीमत 2 हजार रुपये से अधिक थी।

1 फरवरी की सुबह बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलो के इंडेन गैस सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 899.50 रुपये है। वहीं कोलकाता में गैस सिलेंडर की कीमत 926 रुपये है। मुंबई में बिना सब्सिडी वाला घरेली गैस सिलेंडर 899.50 रुपये का है, जबकि चेन्नई में इसकी कीमत अभी 915.50 रुपए है। अगर बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत की बात करें तो इसकी कीमतों में अक्टूबर से ही कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। वहीं नवंबर से लेकर अब तक डीजल-पेट्रोल की कीमतों में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसकी एक बड़ी वजह है यूपी, उत्तराखंड, पंजाब समेत 5 राज्यों मे होने वाले विधानसभा चुनाव। ऐसे में उम्मीद है कि कम से कम चुनाव तक ना तो डीजल-पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी ना ही गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ेगी।

सेंसेक्स के शेयरों में बैंकिंग सेक्टरों में खासी तेजी देखी जा रही है। इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, सन फार्मा, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, अल्ट्राटेक सीमेंट और एलएंडटी के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी आई है। इन शेयरों में एक से दो फीसदी तेजी आई है। दूसरी ओर निफ्टी में ब्रिटानिया में दो फीसदी तेजी आई है। दूसरी ओर सेंसेक्स में डॉ रेड्डीज में गिरावट आई है जबकि निफ्टी में बीपीसीएल, आईओसी, ओएनजीसी और टाटा मोटर्स में एक से तीन फीसदी तक गिरावट आई है। ब्रॉडर मार्केट में बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में भी तेजी आई है। एनएसई में बैंक इंडेक्सेज में एक फीसदी से अधिक तेजी आई है। आईटी, फार्मा और रियल्टी इंडेक्स में भी तेजी आई है।

कार्टून कोना

मुंबई में नाइट कर्फ्यू खत्म, थीम पार्क-स्वीमिंग पूल 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे

- महाराष्ट्र के 11 ज़िलों में पाबंदियों पर ढील

मुंबई, (ईएमएस)। मुंबई समेत महाराष्ट्र के 11 ज़िलों में लगातार कम हो रहे कोरोना संक्रमण की वजह से नियमों और प्रतिबंधों में और ढील दी गई है. कोरोना कंट्रोल में होने की वजह से अब नाइट कर्फ्यू हटा दी गई है. इस बाबत मुंबई मनपा प्रशासन द्वारा मंगलवार को नया दिशा निर्देश जारी किया गया है. इन नए नियमों के तहत मुंबई के सभी पर्यटन स्थल खोल दिए गए हैं. रेस्टोरेंट, नाटकघर और थिएटर 50 फीसदी क्षमता के साथ पहले की तरह ही शुरू करने की इजाजत दी गई है. साप्ताहिक बाजार भी पहले की तरह ही खोले जा सकेंगे. चौपाटी, गार्डन, पार्क शुरू कर दिए गए हैं. स्विमिंग पुल, वॉटरपार्क 50 फीसदी क्षमता के साथ शुरू रहेंगे. वहीं स्पा और सलून भी 50 फीसदी क्षमता के साथ शुरू कर दिए गए हैं. अंतिम संस्कार के लिए अब लोगों की उपस्थिति के लिए कोई शर्त नहीं रखी गई है. यानि अंतिम संस्कार में जितने भी लोग शामिल हो सकते हैं. इसके अलावा धार्मिक कार्यक्रमों में 50 फीसदी लोगों की मौजूदगी की इजाजत दी गई है. शादी के कार्यक्रमों के लिए 25 फीसदी लोगों की उपस्थिति की अनुमति है. खेल के मैदानों में 25 फीसदी लोगों की मौजूदगी की सीमा है. मुंबई में व्यापारियों और उद्यमियों द्वारा लगातार यह मांग की जा रही थी कि कोरोना संक्रमण में लगातार हो रही कमी को देखते हुए प्रतिबंधों में ढिलाई दी जाए. इसे ध्यान में रखते हुए मनपा द्वारा मंगलवार को प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला किया गया है. दरअसल कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत में ओमिक्रॉन के लगातार बढ़ते हुए केस की वजह से इन प्रतिबंधों को लगाया गया था.

- महाराष्ट्र के 11 ज़िलों में पाबंदियों पर ढील

पिछले महीने राज्य में संक्रमण के मामले बेतहाशा बढ़े थे, लेकिन अब इसके दैनिक मामलों में कमी आ रही है. नए दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य के 11 जिलों में पाबंदियों में ढील दी गई है, जहां 90 प्रतिशत से अधिक लोगों ने संक्रमण रोधी टीके की पहली और 70 प्रतिशत लोगों ने टीके की दोनों खुराकें ले ली हैं. जिन 11 जिलों में पाबंदियों में ढील दी गई है वे हैं मुंबई, पुणे, भंडारा, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, रत्नागिरी, सातारा, संगली, गोंदिया, कोल्हापुर और चंद्रपुर.

विरोधियों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए आपराधिक मामले दर्ज नहीं करे

नई दिल्ली (ईएमएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में 23 फरवरी तक गिरफ्तारी से बचाव कर पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार से कड़ी फटकार लगाकर कहा कि लोकतंत्र में सरकारों को चुनाव की पूर्व संध्या पर राजनीतिक विरोधियों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए आपराधिक मामले दर्ज नहीं करने चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और जस्टिस एएस बोपन्ना और हेमा कोहली की पीठ ने बिक्रम सिंह मजीठिया को बड़ी राहत दी। उनके खिलाफ कथित तौर पर 2004 और 2015 के बीच हुए अपराधों के लिए एनडीपीएस अधिनियम के तहत 20 दिसंबर को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले मजीठिया को सुप्रीम राहत मिलने को अकाली दल बड़ी राहत के रूप में देख रही है। बता दें कि अकाली दल ने मजीठिया को अमृतसर ईस्ट से नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है।मजीठिया सिद्धू के कट्टर विरोधी माने जाते हैं।इसके बाद चुनाव से पहले मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलना सिद्धू के लिए मुश्किलें बढ़ने वाला है।

पीठ ने मजीठिया को 23 फरवरी को संबंधित निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने और नियमित जमानत याचिका पेश करने को कहा, जिस पर कानून के अनुसार शीघ्र विचार होगा। सुनवाई के दौरान पीठ ने पंजाब में चुनाव की पूर्व संध्या पर प्राथमिकी दर्ज होने पर चिंता व्यक्त की। इसमें कहा गया है कि एक अन्य विधायक सिमरजीत सिंह बैंस ने भी अग्रिम जमानत याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि राजनीतिक प्रतिशोध और उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने से रोकने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

न्यायमूर्ति रमना के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा, सरकार के आचरण के बारे में यह कहने के लिए खेद है। आज सुबह एक और विधायक सिमरजीत सिंह बैंस का भी जिक्र था। उनके अनुसार, उन्हें रोकने के लिए अंतिम समय पर नामांकन दाखिल करने से पहले प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। हम लोकतंत्र में हैं। कम से कम विरोधियों को नामांकन दाखिल करने और चुनाव लड़ने की अनुमति दें। चुनाव से पहले अचानक ये आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं। इससे सभी को विश्वास होता है कि इसमें राजनीतिक मकसद शामिल है।ठ

राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदंबरम ने कहा, ठतथ्य यह है कि पंजाब आज नशीली दवाओं के व्यापार में डूब रहा है। जब तक हम यह संदेश नहीं भेजते कि नशीली दवाओं के खतरे को गंभीर रूप से नियंत्रित किया जाएगा और इसे राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा, युवाओं का भविष्य पंजाब शापित है। मुझे इस शब्द का उपयोग करने के लिए खेद है।ठ

इसपर सीजेआई ने कहा, आपकी सरकार से मादक पदार्थों के व्यापार के खिलाफ कड़े कदम उठाने से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। जब चुनाव 20 फरवरी को होता है, तो चुनाव से ठीक दो महीने पहले प्राथमिकी दर्ज करना अजीब लगता है।

जन हितैषी

चुनावी घोषणाओं से भरा बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किए बजट में किसानों के लिए सौगातों का पिटारा खोला। बजट में सभी तबके के लोगों का ध्यान रखने की कोशिश की गई। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने इस बजट में किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। इसमें किसानों को डिजिटल सेवा देना, तिलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने का अभियान शुरू किया जाना शामिल है। इसके अलावा पांच नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा, सिंचाई-पेयजल सुविधा बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। हालांकि, 12 करोड़ से अधिक किसानों की उम्मीदों को झटका लगा है। पीएम किसान के 12 करोड़ से अधिक किसानों को उम्मीद थी कि इस बार बजट में पीएम किसान की राशि कम से कम डेढ़ गुनी हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हो सका। नौकरी-पेशा करने वाले लोगों को भी मायूसी हाथ लगी है। सीतारमण ने बजट 2022 में इनकम टैक्स को लेकर कोई भी घोषणा नहीं की। इससे इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव और इनकम टैक्स रेट्स घटाए जाने की उम्मीद लगाए हुए आम लोगों को निराशा ही हाथ लगी है। वित्त मंत्री बजट में वर्क फ्रॉम होम डिडक्शन या स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट में बढ़ोतरी से जुड़ी कोई भी घोषणा नहीं की और न ही स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट में कोई बदलाव किया गया है। बावजूद इसके बाजार ने बजट का दिल खोलकर स्वागत किया। बजट पेश होने के बाद शेयर बाजार में रौनक देखने को मिली। बजट भाषण के दौरान बैंकिंग स्टॉक में जबरदस्त तेजी रही। बजट भाषण के बाद सेंसेक्स करीब 750 अंक मजबूत होकर 58,780 अंक के पार कारोबार कर रहा था। बजट पर सरकार ने किसानों पर खास जोर दिया है। किसान आंदोलन के नुकसान से निपटने सरकार ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। किसानों को डिजिटल सेवा देने, तिलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने, देशभर में गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के ऐलान किए गए हैं। साल 2023 को सरकार ने मोटा अनाज वर्ष घोषित करने का फैसला लिया है। पिछले वर्ष मोटे अनाज को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तार से बात की थी। अब बजट में ऐलान किया गया है कि सरकार मोटे अनाज उत्पादों की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग पर जोर देगी। वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 44 हजार 605 करोड़ रुपए की लागत से केन-बेतवा लिंक परियोजना को शुरू करने का ऐलान किया है। इससे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को राहत मिलेगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए बजट से पहले विशेषज्ञों का अनुमान था कि सरकार के इस बजट में चुनावी राज्यों के लोगों के लिए सौगात होने की संभावना है। खासकर उन किसानों के लिए जो तीन कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। एक साल से ज्यादा वर्षों तक चले किसानों आंदोलन से सरकार पहले ही बैकफुट में है। ऐसे में सरकार ने इस बजट में किसानों के लिए कई योजनाओं का पिटारा खोला है। किसानों के साथ ही आम लोगों को भी सरकार ने राहत दी है। पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण, शहरी क्षेत्रों में 80 लाख नए आवास पूरे किए जाएंगे। इस योजना के लिए सरकार 48,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पहले सिर्फ गरीब वर्ग के लिए था। लेकिन, अब होम लोन की रकम बढ़ाकर शहरी इलाकों के गरीब और मध्यम वर्ग को भी इसके दायरे में लाया गया है। कुल मिलाकर बजट को सर्वहितैषी माना जा सकता है। इसका असर क्या होगा, यह आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा।

बजटः निर्गुण और सगुण दोनों ही

इस साल का जो बजट पेश किया गया है, उसे भाजपा के नेता अगले 25 साल और 100 साल तक के भारत को मजबूत बनानेवाला बजट बता रहे हैं और विपक्षी नेता इसे बिल्कुल बेकार और निराशाजनक घोषित कर रहे हैं। वैसे जब इस बजट को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पेश कर रही थीं तो उनके भाषण को सुननेवाले लोगों को, खासतौर से सामान्य लोगों को लग रहा था कि इस बजट में उनके लिए कुछ नहीं है। सरकार ने न तो रोजमर्रा के इस्तेमाल की कुछ न कुछ चीज़ों को सस्ता करने की घोषणा की है, न आयकर को घटाकर मध्यम वर्ग को कोई राहत दी है और न ही आम लोगों को कुछ मुफ्त सुविधाओं की घोषणा की है। जैसा कि पिछले बजटों के समय जबर्दस्त नौटंकियां होती थीं, वैसी इस बार बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ीं। कुल मिलाकर यह बजट निर्गुण निराकार-सा लगता रहा लेकिन जब इसके सारे आंकड़े अलग से विस्तारपूर्वक सामने आए और टीवी चैनलों पर तरह-तरह की बहसें सुनीं तो लगा कि इस बजट में बुनियादी सुधार के कई ऐसे कदम उठाए गए हैं, जिन्हें सरकार के द्वारा जनता को सरल भाषा में अच्छी तरह समझाना होगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बजट में कहीं भी ऐसी झलक नहीं है कि इसका पांच राज्यों के चुनाव से कुछ संबंध है। हर व्यक्ति यह सोच रहा था कि इन पांचों राज्यों के चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सरकार इस बजट का इस्तेमाल जरुर करेगी। सच पूछा जाए तो किसानों और मध्यम वर्ग के व्यापारियों और नौकरीपेशा लोग तो इस बजट से निराश ही हुए हैं। बड़ी-बड़ी कंपनियां जरुर खुश हुई होंगी कि उनके टैक्स में कटौती हुई है लेकिन सरकार ने जो सपने इस बजट में दिखाए हैं, यदि वह इन्हें ठोस रुप दे सकी तो लोक कल्याण काफी हद तक बढ़ेगा। जैसे वह 60 लाख नए रोजगार देगी, 400 नई रेलें चलाएगी, सारे गंगातटीय प्रदेशों में जैविक खेती को बढ़ावा देगी, 80 लाख मकान गरीबों को देगी, 200 नए टीवी चैनलों द्वारा मातृभाषा के जरिए शिक्षा का प्रसार करेगी, लगभग 4 करोड़ घरों में नलों द्वारा शुद्ध जल पहुंचाएगी, पांच नदियों को जोड़ेगी, 25000 किमी की नई सड़कें बनाएगी, लघु-उद्योगों के प्रोत्साहन में सवा दो लाख करोड़ रु. लगाएगी। इस तरह की घोषणाएं सुनने में तो अच्छी लगती हैं लेकिन इन पर भरोसा तभी होगा जबकि लोगों को इनके ठोस फायदे मिलने लगेंगे। कोरोना महामारी ने करोड़ों लोगों को बेरोजगार किया है और करोड़ों की आमदनी आधी रह गई है, मंहगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है, बहुत-से लोग इलाज के अभाव में मारे गए हैं। ऐसी हालत में अगर इस बजट में आम लोगों को तात्कालिक राहत के कुछ संदेश मिलते तो उसका श्रेय सरकार को भी जरुर मिलता। भारत के लिए 25 और 100 साल के विकास की बात कही गई है लेकिन इस बजट में यदि देश की शिक्षा और चिकित्सा याने मन और तन के सुधार के लिए कोई बुनियादी क्रांतिकारी की पहल इससे होती तो यह बजट सचमुच अन्य बजटों से बेहतर और एतिहासिक भी कहलाता। (लेखक- डॉ. वेदप्रताप वैदिक / ईएमएस)

दैनिक पंचांग

02 फरवरी 2022 को सूर्योदय के समय की ग्रह स्थिति

बुधवार 2022 वर्ष का 33 वां दिन
दिशाशूल उत्तर **ऋतु** शिशिर।
विक्रम संवत् 2078 **शक संवत्** 1943
मास माघ **पक्ष** शुक्ल **तिथि** प्रतिपदा 08.32 बजे तदनन्तर द्वितीया 06.16 बजे प्रातः को समाप्त।
नक्षत्र धनिष्ठा 17.53 बजे को समाप्त।
योग वरीयान 23.58 बजे को समाप्त।
करण बव 08.32 बजे, बालव 19.20 बजे तदनन्तर कौलव 06.16 बजे प्रातः को समाप्त। **चन्द्रायु** 00.8 घण्टे
रवि क्रान्ति दक्षिण 16° 53'
सूर्य उत्तरायन
कलि अहर्गण 1871147
जूलियन दिन 2459612.5
कलियुग संवत् 5123
कल्पारंभ संवत् 1972949123
सृष्टि ग्रहारंभ संवत् 1955885123
वीरनिर्वाण संवत् 2548
हिजरी सन् 1443
महीना जमादि उस्सानी **तारीख** 29
विशेष चन्द्रदर्शन, गुप्त नवरात्रारंभ।

ग्रह स्थिति		लग्नारंभ समय	
सूर्य	मकर में	कुंभ	07.20 बजे से
चंद्र	मकर में	मीन	08.53 बजे से
मंगल	धनु में	मेष	10.24 बजे से
बुध	मकर में	वृष	12.04 बजे से
गुरु	कुंभ में	मिथुन	14.02 बजे से
शुक्र	धनु में	कर्क	16.15 बजे से
शनि	मकर में	सिंह	18.32 बजे से
राहु	वृष में	कन्या	20.43 बजे से
केतु	वृश्चिक में	तुला	22.54 बजे से
राहुकाल		वृश्चिक	01.09 ब.से
12.00 से 1.30 बजे तक		धनु	03.25 बजे से
		मकर	05.30 बजे से

दिन का चौघड़िया		रात का चौघड़िया	
लाभ	05.54 से 07.22 बजे तक	उद्वेग	05.41 से 07.12 बजे तक
अमृत	07.22 से 08.51 बजे तक	शुभ	07.12 से 08.44 बजे तक
काल	08.15 से 10.19 बजे तक	अमृत	08.44 से 10.16 बजे तक
शुभ	10.19 से 11.47 बजे तक	चर	10.16 से 11.47 बजे तक
रोग	11.47 से 01.16 बजे तक	रोग	11.47 से 01.19 बजे तक
उद्वेग	01.16 से 02.44 बजे तक	काल	01.19 से 02.51 बजे तक
चर	02.44 से 04.12 बजे तक	लाभ	02.51 से 04.23 बजे तक
लाभ	04.12 से 05.41 बजे तक	उद्वेग	04.23 से 05.54 बजे तक

चौघड़िया शुभाशुभ- शुभत्व श्रेष्ठ शुभ, अमृत व लाभ, **मध्यम** चर, **अशुभ** उद्वेग, रोग व काल। सभी समय भारतीय मानक समय की मध्य रेखा बिन्दु के आधार पर है अतः आप अपने स्थानीय समयानुसार ही देखें। ■ Jagrutidaur.com, Bangalore

सार्वजनिक पैसे से, निजी गिफ्ट नही दिया जाना चाहिए।

सार्वजनिक पैसे से निजी गिफ्ट दिये जाने के दुष्परिणाम देश के लिए घातक है। चुनाव के दौरान फ्री में बिजली-पानी या अन्य सुविधाऐं देने का वादा करने वाले राजनीतिक दलों के खिलाफ देश के सबसे बड़ी अदालत ने चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा है कि निःसदेह यह गम्भीर मसला है। इससे मतदाता और चुनाव प्रभावित होते हैं, मुफ्त योजनाओं का बजट नियमित बजट से आगे निकल रहा है जो चुनावों की निष्पक्षता को जरूर प्रभावित करता है। राजनीतिक दल उपहार बांटने बिजली-पानी फ्री देने और कई अन्य गैर वाजिब वादे करते हैं। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में बिजली की दर 50 प्रतिशत कम करने, 1 करोड युवाओं को मुफ्त टैबलेट, स्मार्ट फोन, 4.5 करोड श्रमिकों के खाते में 1-1 हजार रूपया, 1 करोड़ निराश्रित महिलाओं के खाते में 1-1 हजार, करोड़ों लोगों को मार्च माह तक फ्री राशन देने का वादा किया है। मुफ्त में महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं योगी आदित्यनाथ की फोटो वाली साड़ी बॉटने वाली खबर तो अखबार में सभी ने पढ़ी है। क्या उत्तर प्रदेश के मतदाता भारतीय जनता पार्टी से यह प्रश्न करेंगे कि मुफ्त में देने वाले उपहार का पैसा वे कहाँ से लायेंगे ? अगर आपने प्रश्न नही किया तो स्पष्ट है कि शराब और नशीली वस्तुओं की बिक्री बढ़ेगी ये चीजें सस्ती होगी परिणाम स्परूप उत्तर प्रदेश में माफिया राज चलेगा महिला हिंसा बेरोजगारी चरम पर होगी।

दुनिया से भारत को सबक सीखना होगा, अमेरिका में सरकार द्वारा निजी उपहार देने पर पाबन्दी है, अमेरिका यह मानता है कि सार्वजनिक पैसे से निजी उपहार नही दिये जाने चाहिए। अगर देश भारत के संविधान से चले तो आर्थिक गैर बराबरी समाप्त हो सकती है, आर्थिक गैर बराबरी आर्थिक हिंसा है, यह देश के नागरिकों को समझाने की आवश्यकता है। चुनाव में निजी उपहार देने के कारण आर्थिक गैर बराबरी बढ़ रही है प्राकृतिक संसाधनों की लूट चरम सीमा पर है, गरीबों की लूट और पूँजीपति को छूट चुनाव में मुफ्त वादे के ही गम्भीर परिणाम हैं। अखबारों पर नजर डालें तो अखबार आर्थिक तंगी के कारण हत्या, लूट, डकैती, धोखाधड़ी के अपराध से भरे पड़े हैं। 24 जनवरी की ही बात है मध्यप्रदेश के सिवनी जिले में चाचा ने 4 साल की बच्ची की हत्या कर लाश दफना दी क्योंकि उसे फिरोती में 3 लाख रूपया प्राप्त नही हुए, आरोपी के परिवार में पत्नि वा दो बच्चे हैं लेकिन बेरोजगार होने के कारण वह आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। शादी एक पवित्र रिश्ता है और ऐसा कहते हैं कि यह रिश्ता जन्मों-जन्मों तक का होता है किन्तु आर्थिक गैर बराबरी के कारण यह रिश्ता कैसे तार-तार हो रहा है। मध्यप्रदेश के सागर जिले में लुटेरी दुल्हन विवाह के 24 घण्टे के भीतर ही ससुराल से मिले जेवर और नगदी लेकर फरार हो गई। बकरीयों की डकैती के बारे में आपने कभी कल्पना भी नही किया होगा लेकिन मध्यप्रदेश के सतना में गरीबों का एटीएम कही जाने वाली बकरीयों पर भी डांका डालकर लुटेरे उसे ले गये। मंदिरों की दानपेटी तथा मंदिर की सम्पत्ति लूटने के लिए मंदिर में डकैती की घटनाऐं आए दिन पढ़ने को मिलती है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। सरकार द्वारा सरकारी नौकरीयों के लिए वैकेन्सी नही निकाली जा रही है, बेरोजगार सड़कों पर रोजगार व नौकरी पाने के लिए उतर रहे हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि नौकरीयों में भ्रष्टाचार से पीढ़ित नव-जवान राष्ट्रीय सम्पत्ति को नुकसान पहुँचा कर, रेल में आग लगाकर रेल्वे की नौकरी में भ्रष्टाचार को उजागर कर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। अगर इसी तरह सरकार द्वारा सार्वजनिक पैसे से निजी उपहार की योजना चलती रही तो बहुत जल्दी हमारा देश वेनेजुएला बन जाऐगा। 1980 में तेल की कीमतें उच्च स्तर पर होने के कारण वेनेजुएला एक अमीर देश था इसके बाद यहाँ की सरकार ने खाने से लेकर पब्लिक ट्रॉस्पोर्ट तक सब मुफ्त कर दिया। 70 प्रतिशत खाने की सामग्री आयात करने लगा। धीरे धीरे आर्थिक स्थित बिगड़ने लगी। इसके बाद तेल की कीमतें गिरने से मंदी आ गई।

सरकार की गलत नीतियों के कारण देश का अन्नदाता आज कर्जे में है उदाहरण के तौर पर लगभग 23 कृषि उत्पाद का समर्थन मूल्य सरकार द्वारा किया गया है किन्तु फसलों की खरीदी समर्थन मूल्य पर ना खरीदे जाने के कारण किसान आज कर्ज में डूबा है, उदाहरण के तौर पर मक्के का समर्थन मूल्य 1870/- रूपये होने के पश्चात् किसानों को 800-1300 रूपये क्विंटल पर मक्का बेचने पर मजबूर होना पढ़ा क्योंकि उसके उपर सोसाईटी, बिजली, बैंक, और साहूकार का कर्ज है। जब मक्का किसान के पास से व्यापारी के पास पहुँच गया तो आज की तारीख में 2022 रूपये क्विंटल में मक्का बिक रहा है इस लूट के खिलाफ सरकार बोलने के लिए राजी नही है। सरकार किसानों को मुफ्त में कुछ भी ना दे लेकिन समर्थन मूल्य पर खरीदी का कानून अवश्य बनाए, उसी तरह उद्योगपतियों द्वारा उत्पादित कृषि उपकरणों का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करें। सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने को तैयार नही है किन्तु उद्यौगपतियों को अधिकतम मूल्य पर बेचने की पूरी छूट एवं सब्सिडी भी देने का काम करती है। संविधान के नीति निर्देशक तत्व में समाज के कमजोर तबके को उठाने के लिए जन कल्याण के माध्यम से कार्यक्रम चला कर कमजोर तबके को ऊँचा उठाने का काम करें तो यह देश हित में होगा। स्व. जयललिता द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को स्कूल जाने हेतु साईकिल उपलब्ध कराना एक जनहित का कार्य था जिसके परिणाम भी देश ने देखे आज स्कूल तथा कॉलेज में पढ़ने वाली गरीब बालिकाओं को मुफ्त परिवहन के पास उपलब्ध कराना देश में बेटियों के ऊर्जा को राष्ट्रीय विकास में जोड़ने के लिए बड़ा योगदान होगा।

सार्वजनिक पैसे से निजी उपहार देने के परिणाम स्वरूप देश का आर्थिक बजट बिगड़ता है। उत्तरप्रदेश में बजट से ज्यदा मुफ्त सौगात की योजनाओं की घोषणा की गई है इसके परिणाम को मतदाताओं को समझना चाहिए, राजस्व को एकत्रित करने के लिए सरकार नशीली वस्तुओं की बिक्री बढ़ायेगी तथा इनकी कीमतें कम करेगी। मध्यप्रदेश इसका उदाहरण है यहाँ शराब सस्ती कर दी गई है सरकार का लक्ष्य है कि 18 साल से अधिक उम्र का हर नव-जवान शराब पीये किन्तु सरकार के लक्ष्य से ज्यदा अब गांव में 7-8 साल का बच्चा भी शराब पीने लगा है। स्कूल में ड्रापआऊट का प्रतिशत बढ़ रहा है। चुनाव में मुफ्त वादे की घोषणा पर देश की सर्वोच्च न्यायालय की अकेले की चिंता से काम नही बनेगा आईये हम सब मिलकर अपने देश को वेनेजुएला बनने से बचाऐं तथा चुनाव में मुफ्त उपहार देने वाली पार्टीयों का बहिष्कार का उनके रजिस्टेशन पर सवालिया निशान उठाऐं। (लेखिका- एड. आराधना भार्गव / ईएमएस)

राजपथ पर दिखी भारत की बढ़ती सैन्य ताकत

राष्ट्रीय गौरव के अवसर गणतंत्र दिवस पर गणतंत्र दिवस परेड भारत की ताकत को पूरी दुनिया के सामने रखने का एक बड़ा अवसर होता है और इस बार परेड में पूरी दुनिया ने राजपथ पर भारत की लगातार बढ़ती ताकत को देखा। गणतंत्र दिवस परेड में आयोजित किए गए रंगारंग कार्यक्रमों के अलावा देश की संस्कृति और परम्पराओं को प्रदर्शित करने के लिए निकाली गई झांकियों तथा पूरे विश्व को भारत की ताकत दिखाने के लिए सेनाओं के जवानों द्वारा किए गए अनोखे करतबों ने हर किसी का मोह लिया। सही मायनों में इस वर्ष परेड में राजपथ पर देश की सांस्कृतिक विरासत और सैन्य शक्ति की झलक स्पष्ट दिखाई दी। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल के चलते इस वर्ष परेड के दौरान होने वाले आयोजनों में कई बदलाव किए गए थे। देश की आजादी के 75 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ, जब परेड 10 बजे के निर्धारित समय के बजाय आधे घंटे देरी से शुरू हुई और परेड का रूट 8.3 किलोमीटर से घटाकर 3.3 किलोमीटर कर दिया गया। परेड में सेना की मार्चिंग टुकडियों से लेकर टैंक, तोप और बैंड के अलावा वायुसेना के फ्लाईपास्ट ने इस आकर्षण में चार चांद लगा दिए। कई विमानों के फ्लाईपास्ट के दौरान भारत के लड़ाकू विमानों का शौर्य पूरी दुनिया को देखने को मिला।

गणतंत्र दिवस परेड के दौरान पहली बार वायुसेना के 75 लड़ाकू विमानों ने राजपथ पर अपनी ताकत दिखाई, जिनमें फ्रांस से आया राफेल भी सम्मिलित था। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए 17 जगुआर विमानों ने 75 के आकार में उड़ान भरते हुए न केवल एक अलग रोमांच पैदा किया बल्कि पूरी दुनिया को भारत की बढ़ती वायुशक्ति का भी परिचय दिया। इस साल की परेड की सबसे विशेष बात यही रही कि इस बार 'आजादी का अमृत महोत्सव' थीम के मद्देनजर ही फ्लाईपास्ट में 39 लड़ाकू जेट विमान, 28 लड़ाकू हेलीकॉप्टर तथा तीनों सेनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल 8 परिवहन विमान शामिल हुए। लड़ाकू जेट राफेल, जगुआर, मिग-29, सुखोई-30, डकोटा, डोर्नियर के अलावा समुद्री टोही विमान पी8आई और चिनूक, एएलएच तथा एमआई-17 हेलीकॉप्टर ने अपनी गर्जना के साथ पूरी दुनिया को भारत की बढ़ती सैन्य ताकत का अहसास कराया। दो चरणों में हुए फ्लाईपास्ट की शुरूआत 4 एमआई-17 हेलीकॉप्टर के साथ 'ध्वज' फॉरमेशन के साथ हुई। इसके बाद 'रूद्र' और 'राहत' फॉरमेशन में क्रमशः 4 व 5 एएलएच (एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर) राजपथ से गुजरे। फ्लाईपास्ट के दूसरे चरण में तीनों सेनाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न विमानों के साथ 13 फॉरमेशन हुए तथा आखिरी फॉरमेशन 'अमृत' में 17 जगुआर लड़ाकू विमान शामिल हुए।

फ्लाईपास्ट में 'वरूण' नामक फॉरमेशन में नौसेना के 2 मिग-29के विमानों के साथ नौसेना के लंबी दूरी के समुद्री टोही विमान पी8आई ने भी उड़ान भरी, जो एलएसी पर चीनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए लद्दाख और उससे पहले डोकलाम में भी तैनात किए गए थे। 'मेघना' फॉरमेशन में एक चिनूक हेलीकॉप्टर तथा चार एमआई-17 ने करतब दिखाए। परेड में 1971 की जंग में भारत की शानदार जीत का प्रतिबिम्ब स्पष्ट परिलक्षित हुआ, जो प्रत्येक भारतीय को गौरवान्वित करने के लिए पर्याप्त था। फ्लाईपास्ट में उड़ान भरने वाले विभिन्न फॉरमेशन को वायुसेना के 1971 की जंग के कई ऑपरेशनों के नामों के आधार पर नाम दिए गए थे। 'टेंगेल फॉरमेशन' फ्लाईपास्ट का अहम हिस्सा रहा, जिसमें एक डकोटा तथा दो डोर्नियर 1971 के युद्ध में टेंगेल एयरड्रॉप ऑपरेशन के लिए श्रद्धांजलि देते हुए विक फॉरमेशन में उड़ान भरते नजर आए। परेड में राफेल विमान सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आए। 'विनाश' फॉरमेशन में पांच राफेल जेट ने दुनिया को भारत की निरन्तर बढ़ती ताकत से रूबरू कराया, वहीं 'बाज' फॉरमेशन में एक राफेल शामिल हुआ, जिसके किनारे दो जगुआर, दो सुखोई-30 तथा दो मिग-29 लड़ाकू विमान उड़ान भरते दिखाई दिए।

भारतीय सेना के 6 मार्चिंग सैन्य दलों में राजपूत रेजीमेंट, असम रेजीमेंट, जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री, सिख लाइट इन्फैंट्री, आर्मी ऑर्डनेंस कोर रेजीमेंट तथा पैराशूट रेजीमेंट भी गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुई। इनके अलावा वायुसेना तथा नौसेना के एक-एक मार्चिंग दल ने भी परेड में हिस्सा लिया। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, बीएसएफ की पांच टुकडियां भी परेड में शामिल हुई। परेड में सेना का प्रतिनिधित्व एक घुड़सवार दल, 14 मशीनीकृत दल, छह पैदल टुकडियों तथा विमानन विंग के उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों के एक फ्लाईपास्ट द्वारा किया गया। इस मशीनीकृत दल में एक पीटी-76 टैंक, एक सेंचुरियन टैंक, दो एमबीटी अर्जुन एमके-आई टैंक, एक एपीसी टोपस बख्तरबंद वाहक, एक बीएमपी-1 पैदल सेना लड़ाकू वाहन और दो बीएमपी-2 पैदल सेना लड़ाकू वाहन दिखाई दिए। एक 75/24 पैक होवित्जर, दो धनुष होवित्जर, एक पीएमएस पुल निर्माण प्रणाली, दो सर्वत्र पुल निर्माण प्रणाली, एक एचटी -16 इलैक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, दो तरण शक्ति इलैक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, एक टाइगर कैट मिसाइल प्रणाली और दो आकाश मिसाइल प्रणाली भी मशीनीकृत दल का हिस्सा बनी।

गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ पर बीएसएफ की महिला टुकड़ी मार्च पास्ट का अहम हिस्सा रही। इसके अलावा 'सीमा भवानी' के नाम से विख्यात महिला बाइकर की टीम ने अपने हैरतअंगेज करतबों से हर किसी को दांतों तले उंगली दबाने को विवश किया। 2015 में पहली बार सेना के तीनों अंगों की पूरी महिला टुकडियों ने मार्च किया था। उसी समारोह में पहली बार सीआरपीएफ के नक्सल विरोधी विशेष बल 'कोबरा' के कमांडो ने भी मार्च किया था। 2016 की परेड में फ्रांसीसी सैन्य दस्ता और 2017 में यूएई का सैन्य दस्ता भी शामिल हुआ था। 2017 की गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार ऐसा हुआ था, जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर पैदल ही राजपथ पर चले थे। उसी परेड में पहली बार पूर्ण स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान 'तेजस' ने आसमान में अपने करतब दिखाए थे। एनएसजी कमांडो का दस्ता भी पहली बार उसी परेड में शामिल हुआ था।

गणतंत्र दिवस परेड में इस वर्ष करीब 1000 ड्रोन, 75 सैन्य विमान और 12 राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों व 9 मंत्रालयों की झांकियां शामिल हुई। परेड में सशस्त्र बलों, केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों, दिल्ली पुलिस, एनसीसी, एनएसएस के 16 पैदल दस्ते, 17 मिलिट्री बैंड तथा विभिन्न राज्यों, विभागों और सैन्य बलों की 25 झांकियां दिखाई दी। परेड में झांकियों के चयन की प्रक्रिया काफी जटिल होती है। इस बार नौसेना की झांकी में देश के स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 1946 के नौसैनिक विद्रोह को दर्शाया गया। कुल मिलाकर राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में परेड के दौरान राजपथ पर भारत की सैन्य ताकत के साथ-साथ देश की सांस्कृतिक झलक भी दिखाई दी। (लेखक- योगेश कुमार गोयल / ईएमएस)

आज का इतिहास 2 फरवरी

1788 भारत में प्रशासनिक सुधार के लिए पिट्स रेग्यूलेटरी अधिनियम लागू किया गया.
1808 फ्रांसीसी फौजों ने रोम पर अधिकार कर लिया.
1814 कलकत्ता संग्रहालय की स्थापना हुई.
1862 मैकाले ने भारत में उच्च शिक्षा को अंग्रेजी से जोड़ दिया.
1862 शंभुनाथ पंडित उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश बने.
1872 हालैंड ने अफ्रीका के गोल्ड कोस्ट में व्यापारिक चौकियां ब्रिटेन को बेच दी.
1878 यूनान ने तुर्की के खिलाफ जंग का ऐलान किया.
1919 पुर्तगाल में राजशाही की घोषणा हुई.
1924 तुर्की की नेशनल असेम्बली ने खलीफा का पद समाप्त किया.
1952 भारत ने टेस्ट क्रिकेट में पहली जीत दर्ज की.
1953 अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड की स्थापना हुई .
1974 कम्युनिस्टों ने कंबोडिया की राजधानी पर बमबारी की जिससे 17 व्यक्ति मारे गए.
1975 इथोपिया की सैनिक सरकार ने इरीट्रिया प्रांत में छापामारों के खिलाफ लड़ाकू विमानों और बख्तरबंद गाड़ियों से कार्रवाई का आदेश दिया.
1977 पश्चिम जर्मनी ने इंडोनेशिया और तुर्की को पनडुब्बी टैंक आदि देने की घोषणा की.
1989 दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पी.डब्ल्यू बोथा ने नेशनल पार्टी के नेता पद से इस्तीफा दिया.
2004 कश्मीर में पुलिस के डीआईजी की मस्जिद में आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या की.

शब्द पहेली - 7185

बाएँ से दाएँ
1. कवि की रचना, गजल-3
3. अनुमान, अंदाज-3
5. सद्पुरुष-2
6. अयोग्य, असंगत -2
8. स्वार्थ, लोभ-4
10. सहयोग, सहकार-3
11. उन्माद, सनक-3
12. भगवान का अराधक-2
13. ठंडक, शीतलता-2
14. दूल्हे के सिर पर बांधी जाने वाली पगड़ी-3
16. चांदी-3
18. गंवारपन, अशिष्टता-4
20. पैंदा, तला-2
22. वर्तमान दिन-2
23. बहने का भाव-3
24. गमन, विदा होना-3

ऊपर से नीचे
1. हुनर, फन, आर्ट-2
2. बल, दम, जोर-3
3. समीप, नजदीक -3
4. गलत का विलोम-2
5. भ्रम, संदेह-3
7. उपनदी, कैनाल-3
8. नशे से भरपूर-4
9. लाख, सौ हजार-2
11. स्वभाव, आदत-4
14. स्वास्थ्य-3
15. इस जगह-2
17. तहजीब, शिष्टता-3
18. इकट्ठा होना-3
19. रेखा, लाइन-3
21. होठ, अधर-2
22. आगमन-2

शब्द पहेली - 7184 का हल

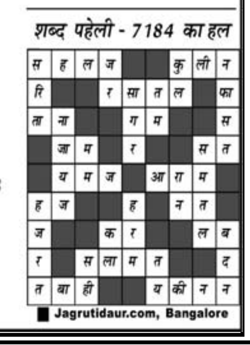

■ Jagrutidaur.com, Bangalore

कार्लसन ने टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज खिताब जीता

विज्क आन ज़ी (ईएमएस)। नॉर्वे के शीर्ष खिलाड़ी मेगनस कार्लसन ने रिकार्ड आठवीं बार टाटा स्टील शतरंज 2022 का खिताब अपने नाम किया है। कार्लसन ने अंतिम दो दौर में अमेरिका के फबियानों करूआना और रूस के डेनियल डुबोव के खिलाफ अंक हासिल करते हुए हुए 13 दौर में कुल 9.5 अंक बनाकर जीत दर्ज की। कार्लसन ने इससे पहले यह खिताब 2008, 2010, 2012, 2015, 2016, 2018 और 2019 में जीते थे। वहीं आठ अंक के साथ ही अजरबैजान के ममेद्यारोव और हंगरी के रिचर्ड रापोर्ट टाईब्रेक के आधार पर दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे जबकि भारत के ही विदित गुजराती को अंतिम दौर में रूस के सेरगी कार्याकिन के हाथों हार का सामना करना पड़ा है। वह 6 अंक के साथ ही 10वें स्थान पर रहे।

खेल - समाचार

सरकार ने खेल बजट बढ़ाया

नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्र सरकार ने मंगलवार को आम बजट में खेलों के लिए भी सौगात दी है। सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए तीन हजार 62 करोड़ 60 लाख रुपये आवंटित किए जो पिछले साल की तुलना में 305 करोड़ 58 लाख रुपये अधिक हैं। पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने खेलों के लिए दो हजार 596 करोड़ 14 लाख रुपये आवंटित किए थे जिसे बाद में संशोधित करके दो हजार 757 करोड़ दो लाख रुपये कर दिया गया था।

माना जा रहा है कि टोक्यो ओलंपिक में खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए ही खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए यह बढ़त की गयी है। आगामी खेल मुकाबलों को देखते हुए ही इन सभी को ध्यान में रखते हुए शायद सरकार ने खेल गतिविधियों पर अधिक खर्च करने का फैसला किया है। बजट में सरकार की अहम योजना खेलो इंडिया कार्यक्रम में 316 करोड़ 29 लाख रुपये का इजाफा किया गया है। खेल इंडिया कार्यक्रम के लिए पिछले बजट में 657 करोड़ 71 लाख रुपये आवंटित किए गए थे तो अब बढ़कर 974 करोड़ रुपये हो गए हैं। वहीं खिलाड़ियों के कुल प्रोत्साहन और पुरस्कार राशि में भी इजाफा किया गया है जो 245 करोड़ से 357 करोड़ रुपये हो गई है।

आईसीसी एकदिवसीय रैंकिंग में भारत की मिताली ओर झूलन को मिला दूसरा स्थान

हीली और जोनासन शीर्ष पर

दुबई (ईएमएस)। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की ताजा एकदिवसीय बल्लेबाजी रैंकिंग में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज एक स्थान के लाभ के साथ ही दूसरे नंबर पर पहुंच गयी हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली नंबर एक स्थान पर है। मिताली के 738 रेटिंग अंक है जबकि हीली 750 अंक लेकर शीर्ष पर है। भारत की ही स्मृति मंधाना 710 अंक लेकर छठे स्थान पर बरकरार है। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो भारत की अनुभवी तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी दूसरे स्थान पर बनी हुई है। ऑस्ट्रेलिया की जोनासन गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर है जिनके 760 अंक है जबकि झूलन के 727 अंक है। ऑस्ट्रेलिया की मेगान शट 717 अंक लेकर तीसरे स्थान पर है। वहीं ऑलराउडरों में इंग्लैंड की नटाली स्किवेर शीर्ष पर पहुंच गयी हैं। ऑस्ट्रेलिया की एलिसे पैरी दूसरे जबकि दक्षिण अफ्रीका की मरियाने काप तीसरे स्थान पर पहुंच गयी हैं। भारत की दीप्ति शर्मा एक पायदान ऊपर आकर चौथे स्थान पर आ गयी हैं।

16 फरवरी से शुरु होंगे रणजी ट्रॉफी मुकाबले

मुम्बई (ईएमएस)। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के अनुसार रणजी ट्रॉफी के लीग मुकाबले 16 फरवरी से शुरु होगें। यह मुकाबले 5 मार्च तक चलेंगे। इससे पहले यह मुकाबले 13 जनवरी से शुरु होने थे पर कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण नहीं हो पाये थे। बीसीसीआई के अनुसार इस टूर्नामेंट में 38 टीम भाग लेंगी और इसके मैच अहमदाबाद, कोलकाता, त्रिवेंद्रम, कटक, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद और राजकोट में खेले जाएंगे। इसके प्रारूप में भी बदलाव किया गया है और इसमें चार टीम के आठ ग्रुप बनाये गये हैं। इसमें प्लेट समूह में छह टीम रहेंगी। देश में जिस प्रकार से संक्रमण के मामले कम हुए हैं उसको देखते हुए ही बोर्ड ने इसके आयोजन का फैसला किया है। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले साल ये मुकाबले नहीं हुए थे। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने हाल ही में कहा था कि इस टूर्नामेंट का आयोजन दो चरणों में होगा। लीग चरण फरवरी और मार्च जबकि नॉकआउट चरण के मैच जून में होंगे। इसका कारण बीच के समय में इंडियान प्रीमियर लीग आईपीएल मैचों का आयोजन है।

अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट सेमीफाइनल में आज होगा भारत-ऑस्ट्रेलिया मुकाबला

शाम 6.30 बजे से शुरु होगा मैच

कूलिज (ईएमएस)। भारतीय जूनियर टीम अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट के सेमीफाइनल में बुधवार को ऑस्ट्रेलियाई अंडर 19 टीम का सामना करेगी। क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश पर मिली शानदार जीत के बाद भारतीय टीम के हौंसले बुलंद हैं। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने विपरीत हालातों के बीच भी अपनी जीत का सिलसिला बनाये रखा। लीग मुकाबले शुरु होने के बाद ही कोरोना संक्रमण के कारण कप्तान यश धुल सहित टीम के छह खिलाड़ी संक्रमित हो गये थे। इसके बाद भी टीम ने जीत का जज्बा बनाये रखा। भारतीय टीम ने अब तक सबसे ज्यादा चार बार यह खिताब जीता है और इस बार उसका लक्ष्य एक और खिताब अपने नाम करना रहेगा। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम ने तीन बार यह खिताब जीता है। भारतीय टीम ने अभ्यास मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम को हराया था जिसका भी उसे मनोवैज्ञानिक लाभ मिलेगा। इसके अलावा पिछले आंकड़ों पर नजर डालें तो भी भारतीय टीम का पलड़ा भारी है। अब तक दोनो के बीच सात मुकाबले हुए हैं, इसमें पांच बार भारतीय टीम जीती है जबकि ऑस्ट्रेलिया को दो बार ही जीत मिली है। इसके साथ ही भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल में हमेशा ही ऑस्ट्रेलियाई टीम पर भारी पड़ी है।

इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को पहले ही मैच में हराकर जीत से शुरुआत की थी। इसके बाद कई खिलाड़ियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद आयरलैंड के खिलाफ भारतीय टीम बड़ी मुश्किल से उतरी थी। 11 इस मैच में कप्तान यश सहित छह खिलाड़ी बाहर थे। ये खिलाड़ी युगांडा के खिलाफ मैच में भी नहीं खेले थे इसके बाद भी भारतीय टीम ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। वहीं अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले के लिए भारत के सभी खिलाड़ी स्वस्थ हैं।

भारत के पास बल्लेबाजी में हरनूर सिंह, अंगकृष रघुवंशी, युश और रशीद जैसे स्टार खिलाड़ी हैं। यश ने पहले मैच में 82 रन बनाए थे। जबकि हरनूर ओर अंगकृष ने आक्रामक बल्लेबाजी कर सबका ध्यान खींचा जै। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो रवि कुमार ने बांग्लादेश के खिलाफ भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। तेज गेंदबाज के तौर पर उसके पास राजवर्धन हंगरगेकर, स्पिनर विकी ओस्तवाल और कौशल तांबे के साथ मध्यम तेज गेंदबाज के तौर पर राज भी हैं।

वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया ने क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को हराया है , ऐसे में उसके कमजोर मानना भूल होगी। उसके पास शानदार सलामी बल्लेबाज टीग वीली है जिन्होंने अब तक बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 71 गेंद में 97 रन बनाए थे। ऐसे में भारतीय गेंदबाजों को इस बल्लेबाज से सावधान रहना होगा। दोनो टीमें इस प्रकार हैं :

भारत : यश धुल (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी, हरनूर सिंह, राज बावा, कौशल ताम्बे, दिनेश भाना, निशांत सिंधू, विकी ओस्तवाल, राजवर्धन हंगरगेकर, वासु वत्स, रवि कुमार।

ऑस्ट्रेलिया : कूपर कोनोली (कप्तान), कैंपबेल केलावे, टीग वीली, एडेन काहिल,कोरे मिलर, जैक सिनफील्ड, टोबियास स्नेल, विलियम साल्जमैन, जैक निसबेट, लाचलान शॉ, टाम व्हाइटनी।

बीसीसीआई खेल विकास महाप्रबंधक मल्होत्रा का इस्तीफा

नई दिल्ली (ईएमएस)। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के खेल विकास महाप्रबंधक धीरज मल्होत्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब मल्होत्रा के आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स में लौटने की संभावना है। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने इसको लेकर कहा , " उन्होंने जनवरी के पहले सप्ताह में ही अपना इस्तीफा दे दिया था।" मल्होत्रा को बीसीसीआई ने पिछले साल फरवरी में सबा करीम की जगह इस पद पर नियुक्त किया था। मल्होत्रा इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी रहे हैं। यह भी पता चला है कि वह एक बार फिर इस फ्रेंचाइजी में किसी शीर्ष पद को संभाल सकते हैं। मल्होत्रा पूर्व में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) में भी कई अहम पदों पर रहे हैं।

वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीतकर सम्मानित अनुभव कर रहा : श्रीजेश

लुसाने (ईएमएस)। भारत पुरुष टीम के अनुभवी गोलकीपर पीआर श्रीजेश को साल 2021 में किये अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। श्रीजेश को कुल 1,27,647 वोट मिले। इससे पहले साल 2019 में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने यह खिताब जीता था। श्रीजेश को इससे पहले एफआईएच गोलकीपर ऑफ द ईयर 2021 भी चुना गया था। इस खिलाड़ी ने कहा कि मैं यह पुरस्कार जीतकर बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। नामांकित करने के लिए भारतीय हॉकी का धन्यवाद। इसके साथ ही उन्होंने वोट देने के लिए दुनिया भर के सभी भारतीय हॉकी प्रेमियों का धन्यवाद दिया है। साथ ही कहा कि नामांकित होने तक मेरा काम था लेकिन प्रशंसकों और हॉकी प्रेमियों ने मुझे यह खिताब दिलाया। यह भारतीय हॉकी के लिए भी एक बड़ा क्षण है क्योंकि दुनिया भर के हॉकी महासंघों ने मुझे वोट दिया है। वहीं हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निंगोमबम ने उन्हें बधाई दी है ओर कहा है कि यह गर्व की बात है।

वहीं 244 मैच खेल चुके और तीन बार के ओलंपियन श्रीजेश ने साथ ही कहा कि मैं व्यक्तिगत पुरस्कारों में विश्वास नहीं करता हूं क्योंकि इसमें खिलाड़ियों के साथ ही कोचिंग स्टाफ, सहयोगी स्टाफ भी शामिल रहता है।

वहीं, श्रीजेश की उपलब्धि पर एफआईएच के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थिएरी वेइल ने कहा कि वैश्विक हॉकी समुदाय की ओर से मैं इस शानदार उपलब्धि के लिए पीआर श्रीजेश को बधाई देना चाहता हूं। यह उनके लिए, उनकी टीम के लिए और समग्र रूप से हॉकी के लिए एक बड़ी पहचान है। हम उन सभी प्रशंसकों को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने उन्हें वोट दिया।

दाऊद का पार्टनर है यूएई में रह रहा पाक कारोबारी, एफएआई ने किया खुलासा

इस्लामाबाद (ईएमएस)। पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी (एफएआई) ने आरोप लगाया है कि खाड़ी में रहने वाला पाकिस्तानी कारोबारी उमर फारूक जहूर मुंबई धमाकों के आरोपी दाऊद इब्राहिम का पार्टनर है। पाकिस्तानी पत्रकार और विश्लेषक रिजवान रजी की ओर से पाकिस्तान में अपलोड किए गए एक वीडियो में दावा किया गया है कि फारूक जहूर वांछित आतंकी दाऊद इब्राहिम का साथी है।

भारत लगातार सवाल उठाता रहा है कि दाऊद कहां है, जबकि पाकिस्तान ने हमेशा यही दावा किया है कि वह पाकिस्तान में नहीं है। रजी ने कहा जांच पाकिस्तानी पुलिस अधिकारी और एफआईए प्रमुख सनाउल्लाह अब्बासी द्वारा दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जहूर दाऊद का साथी है। रजी ने कहा इससे इंटरपोल अब्बासी से पूछ सकता है, क्योंकि कई नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि पाकिस्तान लगातार यही दावा कर रहा है कि दाऊद वहां नहीं है।

रजी ने कहा इस खुलासे के बाद अब्बासी बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। उन्होंने कहा इसके बाद पाकिस्तान को पता नहीं चलेगा कि उसे कहां छिपाया गया है, क्योंकि दाऊद पर गोपनीयता बनाए रखने की उसकी लंबे समय से चली आ रही नीति का उल्लंघन किया गया है। पहले बताया गया था कि नॉर्वे में वित्तीय अपराधों में वांछित एक संदिग्ध जहूर, जिसे अब पूर्व डीजी एफआईए बशीर मेमन के साथ जोड़ा जा रहा है, इमरान खान सरकार के दौरान हाई-प्रोफाइल बैठकों में भाग लेते पाया गया है, आधिकारिक तौर पर जारी किए गए पिक्चर शो से यह साफ हो जाता है।

एफआईए के रिकॉर्ड के अनुसार, उसने 14 वर्षों (2006-2019) में 60 से ज्यादा बार पाकिस्तान का दौरा किया। रिकॉर्ड आगे बताता है कि नार्वे के अधिकारियों द्वारा नियत अवधि के भीतर इंटरपोल के सवालों का जवाब नहीं देने के बाद इंटरपोल ने जहूर के खिलाफ रेड नोटिस रद्द कर दिया था और मेमन ने केवल अर्जी को आगे बढ़ाया था, जब वह (मेमन) डीजी, एफआईए थे।

रिपोर्ट के मुताबिक, यह पता चला है कि अगर जहूर को दंडित करने के प्रयासों का कोई नतीजा नहीं निकलता है, तब एफआईए अपने पूर्व बॉस को एक और जांच में फंसा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जहूर मध्य-पूर्वी राज्य के शाही परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य का करीबी विश्वासपात्र है और पाकिस्तान में महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में मिलने या भाग लेने के दौरान शाही परिवार के सदस्य के साथ अलग-अलग तस्वीरों में उसे देखा गया है।

अब, जैसा कि सरकार प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त किए गए गैरकानूनी आदेश के खिलाफ सार्वजनिक रूप से मेमन के चारों ओर फंदा कसने के लिए तैयार है, जहूर के साथ उसकी तस्वीर को सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें शाही परिवार का सदस्य भी मौजूद था।

बजट में वेतनभोगी, मध्यम वर्ग, गरीब, युवा, और किसानों को कोई राहत नहीं : राहुल गांधी

नई दिल्ली (ईएमएस)। आम बजट को लेकर लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और इसे जीरो सम बजट करार दिया। उन्होंने कहा कि इस बजट में वेतनभोगी, मध्यम वर्ग, गरीब और वंचितों, युवा, किसान और एमएसएमई के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि मोदी सरकार के बजट में कुछ नहीं है। मध्य वर्ग, वेतनभोगी वर्ग, गरीब और वंचित वर्ग, युवाओं, किसानों और एमएसएमई के लिए कुछ नहीं है। आपको बता दें कि सरकार ने इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। जिसको कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भारत का वेतनभोगी वर्ग एवं मध्य वर्ग महामारी, वेतन में चौतरफा कटौती और कमरतोड़ महंगाई के इस दौर में राहत की उम्मीद कर रहा था। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि, टैक्स रिटर्न में अगर कोई गलती हो जाती है तो उसे बाद में सुधारा जा सकता है।

मैक्सिको में साक्षात्कार के समय पत्रकार की हत्या

मैक्सिको सिटी (ईएमएस)। मैक्सिको में ऑनलाइन समाचार संस्थान के पत्रकार की तब गोली मारकर हत्या की, जब पत्रकार वीडियो साक्षात्कार रिकॉर्ड करने की तैयारी कर रहा था।संस्थान के निदेशक ने इसकी जानकारी देकर बताया कि एक महीने के अंदर मैक्सिको में यह चौथे पत्रकार की हत्या है। मिशोएकन नामक संस्थान के उपनिदेशक के कानूनी कार्यालयों में पत्रकार राबर्टो टोलेडो जैसे ही पहुंचे, तीन हथियारबंद लोगों ने उन्हें गोली मार दी। मॉनिटर के निदेशक अर्मांडो लिनारेस ने यह जानकारी देकर बताया कि उनकी भी योजना वहां पहुंचने की थी। पश्चिमी राज्य मिशोएकन में अभियोजकों ने कहा कि वह जिटाकुआरो शहर के एक मामले की छानबीन कर रहे थे। मिशोएकन स्टेट अटॉर्नी कार्यालय ने कहा कि टोलेडो की अस्पताल में मौत हो गई। लिनारेस ने कहा कि टोलेडो ने वीडियो कहानियां रिकॉर्ड कीं और मॉनिटर के लिए दो साल से काम कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि उनका संस्थान संवेदनशील मुद्दों को कवर कर रहा था। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में संगठित अपराध का बोलबाला है और स्थानीय सरकार में अवैध कटाई एवं भ्रष्टाचार जारी है। उन्होंने कहा कि वेबसाइट को सरकारी भ्रष्टाचार पर खबरों के लिए धमकियां मिली थीं। लिनारेस ने कहा, ''भ्रष्ट प्रशासन और भ्रष्ट अधिकारियों और राजनेताओं को बेनकाब करने के लिए आज हमारे एक सहयोगी की जान ले ली गई।'' पत्रकारों की रक्षा के लिए बनी समिति में मैक्सिको के प्रतिनिधि जान अल्बर्ट हूटसेन ने कहा कि टोलेडो 'मॉनिटर मिशोएकन' के लिए कैमरा ऑपरेटर और वीडियो एडिटर के रूप में काम कर रहे थे। टोलेडे घटना के समय मॉनिटर के उपनिदेशक और स्थानीय वकील जोएल वेरा के कार्यालय में उनके नए वीडियो का फिल्मांकन कर रहे थे, तभी हथियरबंद लोग वहां पहुंच गए। राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर के प्रवक्ता जीसस रामिरेज ने कहा कि प्रशासन टोलेडे की हत्या की निंदा करता है।

म्यांमार में सेना के सत्ता में आने के बाद से हिंसा बढ़ी

वाशिंगटन (ईएमएस)। म्यांमार के लिए संयुक्त राष्ट्र की नई विशेष दूत नोलीन हेजर ने दावा किया कि सेना के सत्ता में आने के बाद से हिंसा और क्रूरता बढ़ी है,इसके विरोध में देश में आंदोलन छिड़ गया है। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों ने हिंसा को समाधान के रूप में इस्तेमाल करने'' को लेकर रुख सख्त लिया है। हेजर ने कहा कि म्यांमार की स्थिति तेजी से अस्थिर होती जा रही है, हवाई हमलों सहित सैन्य अभियानों से नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में लगभग 1,500 नागरिक मारे गए हैं और विस्थापित लोगों की संख्या 2021 के अंत के 3,20,000 के आंकड़े से बढ़कर अब 4,00,000 से अधिक हो गई है।उन्होंने कहा, यह एक फरवरी, 2021 से पहले ही विस्थापित हुए 3,40,000 लोगों के अतिरिक्त है, जब सेना ने आन सांग सू ची को सत्ता से बेदखल कर दिया था।

हेजर ने बताया कि म्यांमार की लगभग आधी आबादी वर्तमान में गरीबी के दलदल में है, और 1.44 करोड़ से ज्यादा लोगों को मानवीय सहायता और सुरक्षा की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आसियान के विदेश मंत्री और कुछ नेता पिछले अप्रैल में हुई बैठक में पांच सूत्रीय सहमति को लागू करने के लिए म्यांमार पर दबाव डाल रहे हैं, जिसमें म्यांमा सेना के कमांडर सीनियर जनरल मिन आंग हेइंग भी शामिल हैं। गौरतलब है कि हेइंग ने एक फरवरी 2021 की सुबह सू ची और उनकी सरकार तथा सत्तारूढ़ 'नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी' के शीर्ष सदस्यों को गिरफ्तार करके सत्ता पर कब्जा कर लिया था।

आंग सान सू ची के मामले में सुनवाई 14 फरवरी कों

बैंकाक (ईएमएस)।म्यांमार में अपदस्थ असैन्य नेता आंग सान सू ची के खिलाफ चुनाव धोखाधड़ी मामले में सुनवाई 14 फरवरी को शुरू होगी।म्यांमार में फरवरी 2021 को सैन्य तख्तापलट के बाद सेना ने देश में हुए चुनाव में भारी गड़बड़ी के आरोपों में सू ची को गिरफ्तार किया था। हालांकि स्वतंत्र चुनाव पर्यवेक्षकों का कहना है, कि इन आरोपों के संबंध में उन्हें कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं मिले हैं।

अन्य मामलों में सू ची को छह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। मामले की जानकारी रखने वाले कानूनी अधिकारी ने बताया कि पूर्व नेता पर नवंबर 2020 में हुए चुनाव में केन्द्रीय चुनाव आयोग को प्रभावित करने के आरोप हैं।चुनाव में सू ची की पार्टी 'नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी' से जीत दर्ज की थी। राज्य चुनाव आयोग ने पिछले साल नवंबर में सू ची के खिलाफ चुनाव धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था।

राष्ट्रपति जो बाइडन को जान से मारने की धमकी मिली

वाशिंगटन (ईएमएस)। अमेरिका में मैरीलैंड और कंसास के एक-एक व्यक्ति पर राष्ट्रपति जो बाइडन को जान से मारने की अलग-अलग धमकियां देने का आरोप लगा है। प्राधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। मैरीलैंड के रयान मैथ्यू कॉनलन (37) और कंसास के स्कॉट रयान मैरीमैन (37) को पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया गया था। कॉनलन पर राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के मुख्यालय को बम से उड़ाने की धमकियां देने का भी आरोप लगाया गया है।संघीय प्राधिकारियों ने बताया कि मैरीमैन ने पिछले मंगलवार को अपने गृहनगर में पुलिस को फोन कर कहा कि वह राष्ट्रपति से मिलने के लिए वाशिंगटन डीसी जा रहा है।

यूक्रेन के मुद्दे पर भारत ने चुना बीच का रास्ता, यूएनएससी में मतदान से बनाई दूरी

न्यूयॉर्क (ईएमएस)। भारत ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में यूक्रेन मुद्दे पर हुए मतदान से दूरी बनाए रखी। माना जा रहा है कि भारत इस मुद्दे पर किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहता था। अगर भारत रूस के पक्ष में वोट देता तो इससे अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश नाराज हो सकते थे। वहीं, अगर भारत यूक्रेन के समर्थन करता तो इससे रूस के साथ रिश्तों पर गंभीर असर पड़ सकता था। भारत ने बीच का रास्ता चुनते हुए मतदान से दूरी बना ली।

यूक्रेन और रूस के बीच इस समय युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। रूस ने अपनी सीमा पर एक लाख सैनिकों को भारी हथियारों के साथ तैनात किया हुआ है। वहीं यूक्रेन भी अमेरिका और बाकी नाटो देशों के हथियारों को रूसी सीमा पर भेज रहा है। यूक्रेन मुद्दे पर चर्चा के लिए सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हुई।

बैठक से पहले, रूस, एक स्थाई और वीटो-धारक सदस्य, ने यह निर्धारित करने के लिए एक प्रक्रियात्मक वोट का आह्वान किया कि क्या खुली बैठक आगे बढ़नी चाहिए। रूस और चीन ने बैठक के खिलाफ मतदान किया, जबकि भारत, गैबॉन और केन्या ने भाग नहीं लिया। नॉर्वे, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड, ब्राजील और मैक्सिको सहित परिषद के अन्य सभी 10 सदस्यों ने बैठक के चलने के पक्ष में मतदान किया।

यूएनएससी की बैठक को आगे बढ़ाने के लिए परिषद को केवल नौ वोटों की आवश्यकता थी। परिषद के 10 सदस्यों के बैठक के पक्ष में मतदान करने के साथ यूक्रेन की सीमा पर स्थिति पर बैठक आगे बढ़ी। गौरतलब है कि रूस के यूक्रेन की सीमा के निकट लगभग एक लाख सैनिकों की तैनाती की खबर है। रूस ने इस बात से इनकार किया है कि वह यूक्रेन पर हमला करने की योजना बना रहा है।

अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस-ग्रीनफील्ड ने रूसी राजदूत वासिली नेबेंजिया के इस आरोप को खारिज कर दिया कि वाशिंगटन संकट पर सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाकर कूटनीति का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है। थॉमस ग्रीनफिल्ड ने कहा कि कल्पना कीजिए कि अगर आपकी सीमा पर 100,000 सैनिक होते तो आप कितने असहज होते। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने एक बयान में कहा कि बल प्रयोग को खारिज करने, सैन्य तनाव कम करने, कूटनीति का समर्थन करने और प्रत्येक सदस्य से जवाबदेही की मांग करने के लिए बैठक एक महत्वपूर्ण कदम थी।

उन्होंने कहा देशों को अपने पड़ोसियों के खिलाफ सैन्य आक्रमण से बचना चाहिए। रूस ने इस बात से इनकार किया कि वह हमला करने का इरादा रखता है, लेकिन मांग की कि रूस को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) में शामिल नहीं किया जाए। नाटो और अमेरिका ने इन मांगों को असंभव बताया है।

एफबीआई प्रमुख का आरोप, चीन से पहले के मुकाबले कहीं 'अधिक स्पष्ट' खतरा

वॉशिंगटन (ईएमएस)। वैश्विक संस्था संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) के निदेशक क्रिस्टोफर रे ने चीन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिकी अवधारणाएं और नवोन्मेष चुराने तथा हैकिंग के अभियान चलाने में चीन कई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। एफबीआई प्रमुख का आरोप लगाया और कहा कि पश्चिम को चीन की सरकार से पहले के मुकाबले कहीं 'अधिक स्पष्ट' खतरा है। एफबीआई निदेशक ने 'रोनाल्ड रीगन प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी' में अपने संबोधन में यह बात कही। उन्होंने चीन पर ये अरोप ऐसे वक्त लगाए हैं जब वह शीत ओलंपिक की मेजबानी करने जा रहा है। रे ने अपने संबोधन में यह स्पष्ट किया कि एक ओर जहां अमेरिकी विदेश नीति रूस और यूक्रेन के बीच तनाव से निपटने के रास्ते तलाश कर रही है वहीं वह दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा के लिए चीन को सबसे बड़ा खतरा मान रही है। एफबीआई की ओर से उपलब्ध कराए गए भाषण की प्रति के अनुसार रे ने कहा,'' जब हम अपनी जांचों का मिलान करते हैं, तो पाते हैं कि इनमें से दो हजार से अधिक मामले चीनी सरकार द्वारा हमारी सूचनाओं अथवा प्रौद्योगिकियों को चुराने से जुड़े हैं। ऐसा कोई देश नहीं है जो हमारी अवधारणाओं, नवोन्मेष, और आर्थिक सुरक्षा के समक्ष चीन जैसा व्यापक खतरा पैदा करता है।' रे ने कहा, 'चीन सरकार की आर्थिक जासूसी से नुकसान सिर्फ इतना नहीं है कि उसकी कंपनियां अवैध रूप से प्राप्त तकनीक के आधार पर आगे बढ़ती हैं, बल्कि जब वे आगे बढ़ती हैं, तो वे हमारी कंपनियों और कर्मचारियों को पीछे धकेल देती हैं।' चीन के अधिकारियों ने अमेरिका सरकार के आरोपों को हमेशा खारिज किया है।

यूक्रेन को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रुस और अमेरिका में ठनी

जिनेवा (ईएमएस)। यूक्रेन को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस, अमेरिका का आमना-सामना हुआ। अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस-ग्रीनफील्ड ने रूसी राजदूत वासिली नेबेंजिया के आरोप को खारिज कर दिया कि वाशिंगटन संकट पर सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाकर कूटनीति का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है। थॉमस ग्रीनफिल्ड ने कहा, ''कल्पना करें कि अगर आपकी सीमा पर 100,000 सैनिक होते,तब आप कितने असहज होते।''

खुली बैठक आयोजित करने पर वोट 10-2 से पारित हुआ। रूस और चीन ने विरोध किया, और तीन सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। वोट को मंजूरी के लिए नौ वोटों की जरूरत थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि बल प्रयोग को खारिज करने, सैन्य तनाव कम करने, कूटनीति का समर्थन करने और प्रत्येक सदस्य से जवाबदेही की मांग करने के लिए बैठक एक महत्वपूर्ण कदम थी। उन्होंने कहा कि देशों को अपने पड़ोसियों के खिलाफ सैन्य आक्रमण से बचना चाहिए। रूस ने इस बात से इनकार किया कि वह हमला करने का इरादा रखता है, लेकिन मांग की कि रूस को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) में शामिल नहीं किया जाए।नाटो और अमेरिका ने इन मांगों को असंभव बताया है।

यूक्रेन सीमा पर रूस के 1 लाख सैनिकों का जमावड़ा, बना वैश्विक चिंता का सबब

-अमेरिका भी हजारों सैनिक तैनात करने के लिए तैयार

मास्को (ईएमएस)। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव के बीच रूस ने यूक्रेन की सीमा पर भारी संख्या में सैनिकों को तैनात कर दिया है इसको लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंताएं जताई जा रही हैं। वही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हमले की किसी मंसूबे से इनकार किया है और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने युद्ध की बात से 28 जनवरी, 2022 को इनकार कर चुके हैं। पुतिन ने यूक्रेन की सीमा के पास एक लाख से अधिक सैन्य बल तैनात किए हैं। उधर, अमेरिका हजारों सैनिक तैनात करने के लिए तैयार है। उसने ब्रिटेन और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के सहयोगियों से भी पूर्वी यूरोप में हजारों सैनिक तैनात करने को कहा है। पुतिन ने कहा है कि अगर नाटो यूक्रेन को गठबंधन में शामिल करने से मना कर देता है तो वह पीछे हट जाएगा, लेकिन उसकी यह मांग खारिज कर दी गई है। नाटो क्या है? नाटो 1949 में गठित हुआ एक सैन्य गठबंधन है। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन और आठ अन्य यूरोपीय देशों ने मिलकर यह गठबंधन किया था। अब 30 देश इस संगठन के सदस्य हैं।

यह गठबंधन संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर काम करता है। नाटो और संयुक्त राष्ट्र के बीच कुछ बातें साझा हैं। ये दोनों ही अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जो सदस्य देशों को वित्तीय मदद देते हैं। इन दोनों पर अमेरिका समेत पश्चिमी शक्तियों का राजनीतिक प्रभाव है, लेकिन दोनों संगठन एक जैसे नहीं है। नाटो का काम आवश्यकता पड़ने पर अपने सैन्य सहयोगियों की मदद से युद्ध लड़ना है, जबकि संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षा, राजनीतिक वार्ता और अन्य साधनों के जरिए युद्ध से बचने का काम करता है। यूक्रेन नाटो में शामिल क्यों होना चाहता है? यूक्रेन 1992 के बाद से नाटो का साझेदार है।

नाटो ने 1997 में यूक्रेन-नाटो आयोग की स्थापना करके सुरक्षा चिंताओं पर चर्चा के लिए एक मंच मुहैया कराया है। इसके जरिए एक औपचारिक सदस्यता समझौते के बिना नाटो-यूक्रेन संबंध मजबूत हुए थे। नाटो का सदस्य बनाए जाने पर यूक्रेन के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सैन्य समर्थन बढ़ जाएगा, जो रूसी आक्रामकता को रोकने में मददगार हो सकता है। नाटो गैर-सदस्य देशों को समर्थन देने संबंधी सीमाओं को लेकर स्पष्ट है। हालांकि उसने मानवीय आपात स्थितियों के दौरान अफगानिस्तान जैसे गैर-सदस्य देशों का समर्थन किया है, वह किसी गैर-सदस्य देश में सैनिकों को तैनात करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। नाटो की सदस्यता यूक्रेन को यूरोप की ओर अधिक मजबूती से खींचेगी। इससे यह संभावना बढ़ जाएगी कि यूक्रेन यूरोपीय संघ में शामिल हो सकता है, जो यूक्रेन के लिए एक और नीतिगत लक्ष्य है। इससे यूक्रेन को अमेरिका के साथ और घनिष्ठ संबंध बनाने में भी मदद मिलेगी। साथ ही यूक्रेन से रूस का प्रभाव कम करने में सहायता मिलेगी, लेकिन उसे नाटो की सदस्यता मिलने से क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है।

रूस ने कहा है कि वह गठबंधन के विस्तार को सीधे खतरे के तौर पर लेगा। तो क्या यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाया जा सकता है? यूक्रेन नाटो की सदस्यता हासिल करने की ओर से आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसका इसमें जल्द शामिल होना संभव नजर नहीं आ रहा। किसी देश को शामिल करने के लिए सभी नाटो सदस्यों को सर्वसम्मति से मंजूरी देनी होगी। सदस्यता पाने के इच्छुक देशों को एक सदस्यता कार्य योजना का पालन करना होता है। इसके लिए देशों को अपनी सुरक्षा एवं राजनीतिक नीतियों की विस्तृत जानकारी देनी होती है। योजना को पूरा करने और प्रवेश प्राप्त करने में देश को 20 साल लग सकते हैं, जैसा कि नॉर्थ मैसेडोनिया के मामले में हुआ था। यूक्रेन ने सदस्यता कार्य योजना के लिए 2008 में आवेदन दिया था और यह प्रक्रिया पुतिन समर्थक एवं यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच के कार्यकाल में 2010 में रोक दी गई थी। रूस के साथ बढ़ते तनाव के बीच यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने की योजना को फिर से नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाया है। यदि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिल जाती है, तो उसके और रूस के बीच संघर्ष का खतरा होने पर गठबंधन सदस्य रूस के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे।

बाइडन ने कतर को प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी नामित किया

वाशिंगटन (ईएमएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कतर को एक बड़ा गैर-नाटो सहयोगी नामित किया है। गैर नाटो सहयोगी नामित करने यह मुख्य रूप से एक सांकेतिक सम्मान है, जो अफगानिस्तान से लोगों को निकालने और गाजा में पिछले साल के इजराइल-हमास युद्ध को समाप्त करने में कतर द्वारा की गई सहायता के कारण उसका आभार प्रकट करने के लिए दिया गया है।

बाइडन ने व्हाइट हाउस में कतर के सत्तारूढ़ नेता के साथ एक बैठक के बाद यह घोषणा की। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब यूक्रेन पर रूस के आक्रमण करने के खतरे के बीच यूरोप में ऊर्जा संकट गहराने की आशंका जताई जा रही है और ऐसे में बाइडन पश्चिमी देशों की मदद करने लिए गैस समृद्ध देश कतर की ओर देख रहे हैं। बाइडन ने कतर को बड़ा गैर-नाटो सहयोगी नामित करने की संसद को सूचना देने से कुछ घंटों पहले कहा था, कतर एक अच्छा मित्र और एक विश्वसनीय साझेदार है।

यह कदम एमक्यू-9 रीपर ड्रोन की 50 करोड़ डॉलर से अधिक की बिक्री के लिए अमेरिकी अनुमोदन प्राप्त करने की कतर की कोशिश को सफल बनाने में मददगार साबित हो सकता है। इस संबंधी अनुरोध 2020 से लंबित है। एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने अपना नाम गोपनीय रखने की शर्त पर बताया कि ऊर्जा संकट की स्थिति में कतर द्वारा यूरोपीय सहयोगियों की मदद किए जाने की उम्मीद से इस कदम का कोई लेना-देना नहीं हैं।

उन्होंने कहा अफगानिस्तान और पश्चिम एशिया में कतर से मिली मदद के लिए उसे गैर-नाटो सहयोगी नामित किया गया है। कतर यह दर्जा पाने वाला 18वां देश है। इससे पहले 2019 में ब्राजील को यह दर्जा मिला था। यह दर्जा पाने वाला देश कुछ ऋण कार्यक्रमों का पात्र बन जाता है और उसे सैन्य बिक्री में प्राथमिकता के आधार पर आपूर्ति समेत रक्षा व्यापार और सुरक्षा सहयोग के क्षेत्र में लाभ मिलते हैं। कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी ने कहा हम इन बेहतरीन संबंधों से बहुत खुश और गौरवान्वित हैं। हम हमारे क्षेत्र में शांति स्थापित करने के तरीके खोजने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे।

फ्यूचर समूह की फर्मों की याचिकाओं पर शीर्ष कोर्ट सुनाएगा फैसला

नई दिल्ली (ईएमएस)। देश के सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को फ्यूचर समूह की फर्मों द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर फैसला सुनाएगा, जिसमें अदालत ने सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (एसआईएसी) के आपातकालीन फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए मध्यस्थता आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया गया था। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमना और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने मामले में फैसला सुनाने का समय सुबह साढ़े दस बजे तय किया है। पीठ ने 11 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था और कहा था कि वह रिलायंस रिटेल को एफआरएल की संपत्ति की बिक्री पर रोक लगाने वाले एसआईएसी के आदेश से संबंधित मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय में वापस भेजना चाहती है। शीर्ष अदालत ने एफसीपीएल (फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड) और एफआरएल (फ्यूचर रिटेल लिमिटेड) द्वारा दायर याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रखा है।

विमान ईंधन के कीमतों में 8.5 की रिकॉर्ड उछाल

नई दिल्ली (ईएमएस)। देशभर में विमान ईंधन (एटीएफ) के दामों में रिकॉर्ड उछाल देखी गई हैं। विमान ईंधन की कीमतों में 8.5 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी की गई है। इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच एटीएफ के दाम बढ़ाए गए हैं। जहां जेट ईंधन के दाम एक महीने में तीसरी बार बढ़ाए गए हैं। वहीं पेट्रोल और डीजल कीमतों में रिकॉर्ड 88 दिन से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में एटीएफ का दाम 6,743.25 रुपये प्रति किलोलीटर की वृद्धि के साथ 86,038.16 रुपए प्रति किलोलीटर पर पहुंच गया है। यह एटीएफ कीमतों का रिकॉर्ड स्तर है। इससे पहले नवंबर, 2021 के मध्य में एटीएफ का दाम 80,835.04 रुपये प्रति किलोलीटर की ऊंचाई पर पहुंचा था।

पहली बार रोबोट ने की सफलतापूर्वक सर्जरी

-सूअर की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को दिया अंजाम

वॉशिंगटन (ईएमएस)। विश्व में पहली बार एक रोबोट ने बिना इंसानी मदद के सूअर की सफलतापूर्वक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को अंजाम दिया है। इसके बाद उम्मीद जगी है कि दुनिया में वह दिन दूर नहीं जब रोबोट बिना किसी मदद के इंसान का सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर सकेंगे। अमेरिका के प्रतिष्ठित जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के स्मार्ट टिश्यू ऑटोनॉमस रोबोट ने सूअर के एक टिश्यू पर इस सर्जरी को किया है। शोधकर्ताओं ने पाया कि इंसान की तुलना में रोबोट ने 'ज्यादा बेहतर' तरीके से पशुओं के अंदर इस सर्जरी को किया। अमेरिकी शोधकर्ताओं ने कहा कि यह ऑपरेशन रोबोटिक्स की दुनिया में बहुत बड़ी सफलता है जिससे आगे चलकर अब इंसान का पूरी तरह से स्वचालित ऑपरेशन हो सकेगा। इस ऑपरेशन के जरिए रोबोट ने सूअर की आंत के दो सिरों को जोड़ा। अब तक 4 पशुओं में इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। शोध में कहा गया है कि रोबोट ने ऑपरेशन के दौरान बढिया काम किया जिसमें उच्च दर्जे की कुशलता की जरूरत होती है। शोध के वरिष्ठ लेखक डॉक्टर एक्सेल क्रिएगर ने कहा कि इस ऑपरेशन में दुनिया में पहली बार रोबोट ने बिना किसी इंसानी मदद के ऑपरेशन को किया। पेट में दो आंतों को जोड़ना सबसे चुनौतीपूर्ण कदम होता है और इसके लिए किसी डॉक्टर के विशेषज्ञता की जरूरत होती है।

जरा सी भी असावधानी या हाथ हिला तो दूसरी जगह टांका लग जाएगा और इससे मरीज को गंभीर मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टर एक्सेल क्रिएगर ने लिखा कि हमारा शोध यह बताता है कि हम सर्जरी के एक बेहद कठिन और नाजुक काम आंतों के दो सिरों के जोड़ने को स्वचालित कर सकते हैं। रोबोट ने चार पशुओं में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और इसी ऑपरेशन में इंसानों से बेहतर रिजल्ट दिया।

जापान के मंत्रिपरिषद ने यूनेस्को विरासत के लिए स्वर्ण खदान की नीलामी को दी स्वीकृति

टोक्यो (ईएमएस)। जापान के मंत्रिमंडल ने मंगलवार को युद्ध के समय के लिए श्रम से जुड़ी एक विवादास्पद पूर्व सोने की खदान को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए नीलामी की मंजूरी दे दी। एक स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के हवाले से यह जानकारी मिली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कूटनीतिक रूप से विवादास्पद बोली को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई।

टोक्यो बाद में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर को अनुशंसा पत्र देने की योजना बना रहा है। 27 जनवरी को, जापानी प्रधान मंत्री फुमियो किशिदा ने दक्षिण कोरिया के कड़े विरोध के बावजूद 2023 यूनेस्को विरासत सूची के लिए साडो द्वीप पर खदान को नामित करने की योजना की घोषणा की। दक्षिण कोरियाई सरकार ने तुरंत इस फैसले पर कड़ा खेद व्यक्त किया और सियोल में अपने राजदूत कोइची आइबोशी को विरोध दर्ज करने के लिए बुलाया।

निगाटा प्रान्त में साडो द्वीप पर खदान में एक हजार से अधिक कोरियाई लोगों को कड़ी मेहनत के लिए मजबूर किया गया था। इस कदम से साझा इतिहास को लेकर सियोल और टोक्यो के बीच राजनयिक दरारें और गहरी हो सकती है।

बजट के बाद हुई खरीददारी से उछला शेयर बाजार

सेंसेक्स 848 अंक , निफ्टी 237 अंक ऊपर आया

मुंबई (ईएमएस)। मुम्बई शेयर बाजार मंगलवार को बढ़त के साथ बंद हुआ। सप्ताह के दूसरे ही कारोबारी दिन बाजार में यह तेजी आम बजट में बुनियादी ढांचे पर जोर देने के साथ ही धातु और पूंजीगत सामान कंपनियों के शेयरों में भारी खरीदारी के अलावा दुनिया भर के बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों से आई है। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सूचकांक 59,032.20 की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद 848.40 अंक करीब 1.46 फीसदी बढ़कर 58,862.57 पर बंद हुआ। वहीं इसी प्रकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 237 अंक तकरीबन 1.37 फीसदी ऊपर आकर 17,576.85 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में सबसे अधिक 7.57 फीसदी की बढ़त टाटा स्टील के शेयरों में रही। इसके अलावा सन फार्मा, इंडसइंड बैंक, एलएंडटी, अल्ट्राटेक सीमेंट, आईटीसी और एचसीएल टेक के शेयर भी ऊपर आये हैं।

वहीं दूसरी ओर महिंद्रा एंड महिंद्रा, पावरग्रिड, एसबीआई, भारती एयरटेल, एनटीपीसी, मारुति और रिलायंस के शेयरों को नुकसान हुआ है। इससे पहले सुबह बाजार बढ़त के साथ खुला था। शुरुआती कारोबार में ही सेंसेक्स 600 अंक से अधिक बढ़ा जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (निफ्टी) में 159 अंक की बढ़त आई थी। सेंसेक्स में सबसे अधिक 2.45 फीसदी की बढ़त इंडसइंड बैंक में हुई। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी ट्विन्स, सन फार्मा, इंफोसिस, कोटक बैंक और बजाज फिनसर्व के शेयर भी ऊपर आये हैं।

वहीं दूसरी ओर आईटीसी और पॉवरग्रिड के शेयर नुकसान के साथ ही लाल निशान पर थे। इससे पहले गत सत्र में सेंसेक्स 813.94 अंक करीब 1.42 फीसदी की बढ़त के साथ ही 58,014.17 अंक जबकि निफ्टी 237.90 अंक बढ़कर 17,339.85 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

'नियोकोव' फैला तो मचा देगा भारी तबाही

-चीन के अनुसंधानकर्ताओं ने दी चेतावनी

पेइचिंग (ईएमएस)। 'नियोकोव' कोरोना वायरस अगर और ज्यादा उत्परिवर्तित हुआ तो यह मानव में भारी तबाही मचा सकता है। यह चेतावनी दी है चीन के अनुसंधानकर्ताओं ने। यह अध्ययन प्रकाशन पूर्व संग्रह कोश बायोआरएक्सआईवी पर हाल में डाला गया है और इसकी समीक्षा की जानी अभी बाकी है। अध्ययन से यह पता चलता है कि नियोकोव 'मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम' (मर्स) से करीबी रूप से संबद्ध है।

विषाणु जनित इस रोग की पहली बार 2012 में सऊदी अरब में पहचान की गई थी। कोरोना वायरस विषाणुओं का एक बड़ा परिवार है, जो सामान्य सर्दी जुकाम से लेकर सार्स जैसे रोग का कारण बन सकता है। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज और वुहान यूनिवर्सिटी के अनुसंधानकताओं ने यह गौर किया है कि नियोकोव दक्षिण अफ्रीका में चमगादड़ों के समूह में पाया गया है और यह इन जंतुओं में विशेष रूप से फैलता है।अनुसंधानकर्ताओं ने इस बात का जिक्र किया कि अपने मौजूदा स्वरूप में नियोकोव मानव को संक्रमित नहीं करता है, लेकिन अगर यह और अधिक उत्परिवर्तित हुआ, तो यह संभवतः नुकसानदेह हो सकता है। अनुसंधानकर्ताओं ने कहा, 'इस अध्ययन में, हमने अप्रत्याशित रूप से पाया कि नियोकोव और इसके करीबी संबंधी पीडीएफ- 2180-कोव, मानव शरीर में प्रवेश करने के लिए कुछ प्रकार के बैट (चमगादड़) एंजियोटेंसिन कंवर्टिंग एंजाइम 2 (एसीई 2) का प्रभावी रूप से उपयोग कर सकते हैं।'

एसीई 2 कोशिकाओं पर एक रिसेप्टर प्रोटीन है, जो कोरोना वायरस को कोशिकाओं से जुड़ जाने और संक्रमित करने के लिए प्रवेश बिंदु प्रदान करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह नियोकोव कोरोना वायरस मर्स कोव वायरस से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले साल 2012 और 2015 में पश्चिम एशिया के देशों में इसके प्रकोप का पता चला था। यह सार्स कोव-2 की तरह से जिससे इंसानों में कोरोना वायरस का संक्रमण होता है।

दुनिया की सबसे लग्जरी बिल्डिंग होने के बाद भी सीवेज सिस्टम से नहीं जुड़ी बुर्ज खलीफा, रोजाना करनी पड़ती है सफाई

दुबई (ईएमएस)। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) स्थित दुबई दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है। इस रेगिस्तानी महानगर की सबसे आकर्षक चीज दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है। चमचमाती हुई यह कांच की बिल्डिंग दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, जिसकी लंबाई 830 मीटर है। इस बिल्डिंग में हर सुख-सुविधा मौजूद है। लेकिन इस इमारत की एक सबसे बड़ी कमी है इसका सीवेज सिस्टम। दुनिया की सबसे लग्जरी बिल्डिंग होने के बावजूद यह दुबई के सीवेज सिस्टम से जुड़ी नहीं हैं।

लिहाजा इसके सीवेज को साफ करने का तरीका बेहद पुराना और 'गंदा' है। हर रोज गंदगी साफ करने वाले ट्रकों की कतार इस झिलमिलाते आलीशान टॉवर में आती है और इमारत के सीवेज को ट्रकों में भरकर ले जाया जाता है। यहां से इस कचरे को शहर से बाहर ले जाया जाता है।

सीवेज की व्यवस्था सुनिश्चिति किए बिना एक गगनचुंबी इमारत पर 1.5 अरब डॉलर कैसे खर्च कर दिए गए? दरअसल, जब बुर्ज खलीफा का काम पूरा हुआ तो दुबई 2008 के आर्थिक संकट के प्रभावों से जूझ रहा था। लिहाजा यह फैसला लिया गया कि इसे शहर के पहले से ही गड़बड़ी से जूझ रहे सीवर सिस्टम में जोड़ने की लागत, पैसे की अनावश्यक बर्बादी थी। निर्माताओं को विश्वास था कि सीवर सिस्टम में सुधार करने की तुलना में हर दिन कचरे को बाहर निकालना एक सस्ता विकल्प होगा।

हालांकि 35000 लोगों की निवास क्षमता के साथ, इमारत एक दिन में 15 टन सीवेज का चौंका देने वाला उत्पादन करने में सक्षम है। अब सीवेज सिस्टम को फिर से विकसित करने की योजना है, लेकिन यह काम 2025 तक पूरा नहीं होगा। इस लिए जब आप बुर्ज खलीफा जाएं तो नारंगी ट्रकों के काफिले पर नजर रखें और जब ये दिखें तो खिड़कियां बंद कर लें।

जन हितैषी

अहमदाबाद के 11 स्वास्थ्य संस्थानों में PSA ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट कार्यरत : मुख्यमंत्री

- महानगर पालिका द्वारा 20 करोड़ रुपए के ख़र्च से तैयार किए गए 19 PSA ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का किया ई-लोकार्पण

अहमदाबाद (ईएमएस) कोरोना की तीसरी लहर का सामना करने की तैयारी के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने प्रत्येक राज्य को ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के निर्देश दिए थे। इस निर्देश के तहत अहमदाबाद महानगर पालिका द्वारा 3 बड़े जनरल अस्पतालों, 9 कम्युनिटी हेल्थ सेंटरों तथा 1 कोविड केयर सेंटर में इ्रईं ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित करने का कार्य शुरू किया गया था। तद्अनुसार 2000 थ्इ्श, 1000 थ्इ्श तथा500 थ्इ्श; इन अलग-अलग कैपेसिटी के कुल 19 प्लांट स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा 20 करोड़ रुपए के ख़र्च से तैयार किए गए इन अलग-अलग क्षमताओं वाले कुल 19 इ्रईं ऑक्सीजन जनरेशनल प्लांट का मंगलवार को ई-लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस अवसर पर कहा कि पूरा विश्व कोरोना महामारी की तीसरी लहर के विरुद्ध संघर्ष कर रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी के नेतृत्व में हमने विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन शुरू किया और देशवासियों को रक्षा कवच प्रदान किया है। गुजरात में टीकाकरण अभियान के अंतर्गत लोगों को टीके दिए जाने से अब तक तीसरी लहर के संक्रमण में काफ़ी कमी पाई गई है। उन्होंने कहा कि गुजरात में नागरिकों को अब तक 9 करोड़ 76 लाख 86 हज़ार 539 वैक्सीन डोज़ दी गई हैं। इसके बावजूद राज्य सरकार ने पूर्व आयोजन के तहत इ्रईं प्लांट की सुविधा व्यापक बनाई है। दुनिया के विकसित व आधुनिक शहरों में माने जाने वाले अहमदाबाद के नगरजनों को आज उनकी स्वास्थ्य-सुश्रुषा में वृद्धि के लिए एक साथ 19 ऑक्सीजन प्लांट प्राप्त हो रहे हैं। अहमदाबाद महानगर पालिका द्वारा 20 करोड़ रुपए के ख़र्च से तैयार किए गए इन प्लांट को अहमदाबाद के 3 बड़े जनरल अस्पतालों, 9 कम्युनिटी हेल्थ सेंटरों तथा एक कोविड केयर सेंटर में लगाया गया है। 5000 से 2000 लीटर की क्षमता वाले ये प्लांट आवश्यकता के समय मरीज़ों की ऑक्सीजन की मांग पूरी करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मेडिकल ऑक्सीजन की मांग बहुत बढ़ी थी, जिसके कारण नए ऑक्सीजन प्लांट की आवश्यकता उत्पन्न हुई थी। सौभाग्य से तीसरी लहर के दौरान ऐसी किसी स्थिति का निर्माण नहीं हुआ है। इसका कारण है गुजरात में चल रहा व्यापक टीकाकरण अभियान। टीकाकरण के परिणामस्वरूप राज्य में आज कोरोना मरीज़ों का हॉस्पिटलाइज़ेशन कम हुआ तथा ऑक्सीजन की ज़रूरत भी कम पड़ी है। तीसरी लहर में कोरोना से ज़्यादातर ऐसे लोग प्रभावित हुए हैं, जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है। वैक्सीन नहीं लिए जाने के कारण शरीर में कोरोना के विरुद्ध शरीर की रोगप्रतिकारक शक्ति विकसित न होना स्वाभाविक है। ऐसे बहुत कम मामले देखने को मिल रहे हैं, जिनमें कोरोना संक्रमितों को वेंटिलेटर पर रख कर ऑक्सीजन देनी पड़ी हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी ने चुनौतियों से निपटने की क्षमता दी है। कोरोना की दो लहरों की दीव्रता के दौरान ऑक्सीजन की आपूर्ति को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों ने चुनौती के रूप में स्वीकारा और सरकार का समग्र प्रशासन इस कार्य में जुटा तथा देश भर में ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई गईं। एयरफ़ोर्स के विमानों तथा नौसेना के जहाज़ों की भी मदद ली गई। केन्द्र सरकार ने रेलवे के सहयोग से 424 से अधिक ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनें चलाईं और देश के विभिन्न राज्यों में 1748 से अधिक टैंकरों से लगभग 30455 मैट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की पहली दो लहरों के अनुभव से हमने गुजरात के अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की व्यवस्था के मामले में आत्मनिर्भर बनने का आयोजन किया, जिसकी तैयारी के अंतर्गत हाल में राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में 445 इ्रईं प्लांट कार्यरत् हैं तथा पीएम केयर्स फ़ंड के अंतर्गत गुजरात के लिए 89.91 मैट्क टन क्षमता वाले 59 प्लांट कार्यरत हो चुके हैं। इनमें सभी सांसदों व विधायकों के फ़ंड से भी 55 इ्रईं प्लांट राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों को प्राप्त हुए हैं। इनकी ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता लगभग 31.39 मैट्रिक टन है। उन्होंने कहा कि 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' वर्ष में प्रधानमंत्री ने 'आत्मनिर्भर भारत' का संकल्प दिया है। हमें 'आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत' बनाना है। गुजरात ने मेडिकल ऑक्सीजन के जनरेशन, स्टोरेज तथा आपूर्ति के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी ने देश के हेल्थ इनस्ट्रक्चर को अधिक आधुनिक बनाने के लिए अनेक क़दम उठाए हैं। प्रधानमंत्री ने स्वदेशी मास वैक्सीनेशन, दवाइयों-ऑक्सीजन का उत्पादन तथा राज्यों को भी स्वास्थ्य रक्षा कवच तैयार करने के लिए निरंतर मार्गदर्शन दिया है। भूपेंद्र पटेल ने कहा कि वर्तमान कोरोना महाहारी के चलते देश और दुनिया को ऑक्सीजन का महत्व समझ में आया है। लोगों में ग्रीन कवर बढ़ा कर प्राकृतिक प्राण वायु के प्रति समझ बढ़ी है। वायु, जल एवं भूमि प्रदूषण और क्लाइमेंट चेंज के दुष्प्रभावों को टालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी ने देश को क्लीन-ग्रीन एनर्जी का नया मार्ग दिखाया है। उनकी बनाई पगडंडी पर चल कर गुजरात पीएसए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की स्थापना, टीकाकरण अभियान, ग्रीन एनर्जी उपभोग क्षेत्र में समग्र देश में हाल में अग्रसर है। मुख्यमंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि हम सभी को राज्य के सभी नागरिकों का स्वास्थ्य सुरक्षित रखने की स्थिति का निर्माण करना है। इस अवसर पर अहमदाबाद के महापौर किरीटकुमार परमार ने 20 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए 19 पीएसए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के विषय में जानकारी दी। ऑक्सीजन प्लांट कार्यरत् होने से अस्पतालों के 1393 बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध होगी और लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति का बोझ घटेगा। इनमें एञ्ङमें 6, एल. जी. अस्पताल तथा शारदाबेन अस्पताल में 1-1, समरस अस्पताल में 2 तथा 9 कम्युनिटी हेल्थ सेंटरों में 9 इ्रईं प्लांट कार्यरत किए गए हैं। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री रुषिकेशभाई पटेल, कुटीर उद्योग मंत्री जगदीशभाई विश्वकर्मा, अहमदाबाद महानगर पालिका आयुक्त लोचन शहेरा, उप महापौर श्रीमती गीताबेन पटेल, सांसद एवं विधायक भी उपस्थित रहे।

किशन भरवाड केस में नया खुलासा

२००२ के हमले का बदला लेने के लिए मौलाना ने हत्या कराई

अहमदाबाद, १ फरवरी ।

धंधुका के किशन भरवाड हत्या केस में बड़ा खुलासा सामने आया है । वर्ष २००२ में मौलाना एयुब पर गांधीनगर में हमला हुआ था और इसका बदला लेने के लिए उसने ऐसा किया हो इसकी आशंका है ।

महत्व का है कि, मौलाना एयुब द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई है और जो जो पुस्तक जझबाते शहादत नाम की है । पुस्तक भी आशंका के घेरे में आ गई है । दिसंबर महीने में इस पुस्तक का विमोचन हुआ था । विमोचन में उस्मानी और शब्बीर भी मौजूद था । अब गुजरात एटीएस यह पुस्तक को लेकर जांच कर रही है कि पुस्तक में क्या लिखा है, कोई विवादित लिखा है कि नहीं । धंधुका किशन हत्या केस मामले में जांच तेज हुई है । ज्यादा लोगों को जांच के लिए एटीएस लाया गया है । घटना की प्लानिंग कब हुई इसकी भी जांच शुरू की जा रही है ।

अजीम हथियार जहां से लाया इसे लेकर भी कार्रवाई शुरू की गई है । एटीएस की टीम मौलाना को जमालपुर जांच के लिए ले गई थी । जमालपुर की मदरेसा से भड़काऊ लिखा हुई पुस्तक और एयरगन भी मिल गया है । किशन मर्डर केस के आरोपी ऐसा मौलाना एयुब के घर निकट के मदरेसा से एक एयरगन और धार्मिक पुस्तक मिल गया है । आरोपी शब्बीर उर्फ शाबा चोपडा और इम्तियाज पठान गोली मारकर किशन भरवाड की हत्या की । किशन भरवाड ने २० दिन पहले सोशल मीडिया पर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे ऐसी पोस्ट वायरल की थी । जिसे लेकर किशन के विरूद्ध शिकायत भी दर्ज कराई गई थी । यह केस में किशन को जमानत मिल गया और समाधान भी हुआ । लेकिन कट्टरवादी मानसिकता वाले शब्बीर को समाधान मान्य नहीं था । आरोपी ने २० जनवरी को दोस्त इम्तियाज के साथ किशन भरवाड का पीछा करके इस पर दो राउंड फायरिंग करके हत्या कर दी । दोनों आरोपियों की पूछताछ में सामने आया कि, शब्बीर की कट्टरवादी विचारधारा है ।

सेवा भारती अहमदाबाद द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर साउथ भोपाल में भव्य आयोजन

अहमदाबाद, 73 वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सेवा भारती अहमदाबाद द्वारा शहर के साउथ बोपल में एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में साउथ बोपल के संघ सह संचालक श्री श्याम सुंदर जी एवं कर्मा फाउंडेशन की श्रीमती वर्षा जी की गरिमामय उपस्थिति रही।

इस अवसर पर यह जानकारी देते हुए श्रीमती नूतन जोशी ने बताया कि बच्चों में देश प्रेम की भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान नन्हे बच्चों द्वारा देश भक्ति से ओतप्रोत कविता, गीत व नृत्य की शानदार प्रस्तुतियां दी गईं। जो सभी के आकर्षण के केंद्र रहें कार्यक्रम का सफल संचालन श्रीमती नूतन जोशी एवं श्री समीर शाह द्वारा किया गया।

प्रेमी ने विवाहिता के साथ जबरदस्ती से संबंध बनाया निजी पल के विडियो और तस्वीरें वायरल कर देने की धमकी देने वाले प्रेमी के खिलाफ महिला ने शिकायत दर्ज कराई

अहमदाबाद, १ फरवरी ।

शहर की एक विवाहिता ने सोला पुलिस स्टेशन में प्रेमी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी । जिसमें उसने इसके खिलाफ जबरदस्ती से शारीरिक संबंध बनाये होने की और इसकी निजी विडियो तथा तस्वीरें खींचकर ब्लैकमेल करते होने का आरोप लगाया था । कुछ वर्ष पहले महिला की शादी इसके ही समाज के युवक के साथ हुई थी, हालांकि दोनों के बीच मतभेद होने पर वह अलग हो गये थे । जिसके बाद महिला ने अन्य युवक के साथ शादी की थी, इस दौरान वह तीसरे युवक के प्रेम में थी । सोला में रहती महिला ने पुलिस के समक्ष दर्ज कराई शिकायत में बताया है कि, इसकी शादी इसके समाज के युवक के साथ हुई थी । एक ही वर्ष में दोनों के बीच मेलमिलाप नहीं होने पर उन्होंने परिवार की मंजूरी से अलग होने का निर्णय लिया था । पहले पति से अलग होने के बाद महिला की माइके निकट रहते युवक के साथ दोस्ती हो गई थी । इसकी पत्नी की मौत हुई होने से वह भी जीवनसाथी की खोज में था । जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली थी और उनका घरसंसार भी अच्छे तरीके से चल रहा था । दूसरे पति के साथ वैवाहिक जीवन के दौरान महिला तीसरे युवक के प्रेम में पड़ी थी । उसने शिकायत में कहा कि, एक दिन जबकि वह घर में अकेली थी तब इसका प्रेमी घर पर पहुंच गया था और इसने इसके साथ जबरदस्ती से संबंध बनाया था । इतना ही नहीं इसने निजी पल का विडियो बना लिया था और तस्वीरें खींच ली थी । जिसके बाद वह अक्सर महिला को होटेल और गेस्टहाउस में जबरदस्ती बुलाता था और इसके साथ संबंध बनाता था । महिला जबकि इसके बीमार पिता की खबर लेने गई तब भी प्रेमी के पीछे पीछे पहुंच गया था और यहां भी संबंध बनाया था । जबकि महिला संबंध बनाने से इनकार करती थी तब प्रेमी इसे विडियो और तस्वीरें वायरल कर देने की धमकी दी थी । जिसके बाद इसने परेशान होकर सोला पुलिस स्टेशन में प्रेमी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी ।

गुजरात में कोरोना के फिर बढ़े मामले, 8338 नए मरीज, 16629 हुए ठीक, 38 मौतें

अहमदाबाद (ईएमएस) गुजरात में सोमवार के मुकाबले मंगलवार को कोरोना के दैनिक केसों की संख्या में वृद्धि हुई हैं सोमवार को राज्य में कोरोना के 6679 नए केस दर्ज हुए थे, वहीं मंगलवार को यह संख्या बढ़कर 8338 हो गईं हांलाकि कोरोना से स्वस्थ होने का दर बढ़ रहा है, लेकिन मृतांक थम नहीं रहा आज राज्यभर में कोरोना से 38 मरीजों की मौत हो गईं राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने का दर 92.65 प्रतिशत हैं मंगलवार को राज्य में 4.49 लाख से ज्यादा नागरिकों का टीकाकरण किया गया स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अहमदाबाद कॉर्पोरेशन में 2654, वडोदरा कॉर्पोरेशन में 1712, वडोदरा में 484, राजकोट कॉर्पोरेशन में 475, सूरत कॉर्पोरेशन में 257, पाटन में 224, गांधीनगर कॉर्पोरेशन में 223, बनासकांठा में 212, कच्छ में 210, राजकोट में 160, भरुच में 145, सूरत में 137, मेहसाणा में 130, मोरबी में 116, खेडा में 112, पंचमहल में 98, आणंद में 95, जामनगर कॉर्पोरेशन में 95, साबरकांठा में 84, वलसाड में 81, भावनगर कॉर्पोरेशन में 80, गांधीनगर कॉर्पोरेशन में 64, अमरेली में 61, अहमदाबाद में 48, जूनागढ़ कॉर्पोरेशन में 46, नवसारी में 39, गिर सोमनाथ में 37, सुरेन्द्रनगर में 37, तापी में 34, दाहोद में 33, जूनागढ़ में 30, जामनगर में 21, छोटाउदेपुर में 16, देवभूमि द्वारका में 16, महीसागर में 16, डांग में 13, नर्मदा में 11, अरवल्ली में 10, बोटाद में 5 और पोरबंदर में 5 समेत राज्यभर में कोरोना के 8338 नए केस दर्ज हुए जबकि 16629 लोगों को डिस्चार्ज किए जाने के साथ ही राज्य में अब तक 1083022 नागरिक कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं मंगलवार को राज्य में 38 मरीजों की मौत के साथ राज्य में कोरोना का मृतांक 10511 पर पहुंच गया फिलहाल राज्य में 75464 एक्टिव केसों में 75235 स्टेबल हैं और 229 मरीज वेन्टीलेटर पर हैं मंगलवार को राज्य में 449165 नागरिकों के टीकाकरण के साथ राज्य में अब तक कुल 9 करोड़ 83 लाख 82 हजार 401 लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका हैं

कोरोना के दौर में केन्द्र सरकार का बजट ऊंट के मुंह में जीरा : अर्जुन मोढवाडिया

अहमदाबाद (ईएमएस) केन्द्र सरकार के आज पेश किए गए बजट को लेकर गुजरात प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रमुख अर्जुन मोढवाडिया की प्रतिक्रिया सामने आई हैं केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा लोकसभा में पेश 2022-23 के बजट को मोढवाडिया ने कोरोना के विकट दौर में ऊंट के मुंह में जीरा करार दिया और कहा कि बजट को लेकर अपेक्षा थी कि ठप हो चुके अर्थतंत्र को रफ्तार मिलेगी, महंगाई उन्मूलन और रोजगार के अवसरों के सृजन की घोषणा की जाएगी लेकिन इन सभी आशाओं पर केन्द्रीय बजट ने पानी फेर दिया हैं मोढवाडिया ने कहा कि केवल कॉर्पोरेट सेक्टर के पूंजीपति लोगों को टेक्स में राहत दी गई है, परंतु जीएसटी की 1.40 लाख करोड़ रुपए की ऐतिहासिक आय के बावजूद आयकर में कोई राहत नहीं देकर मध्यम वर्ग को बड़ा झटका दिया हैं बजट में किसानों के लिए एमएसपी के प्रावधाव और आय बढ़े इसकी घोषणाओं की उम्मीद थी, उसमें भी निराशा हाथ लगी हैं जीवनजरूरी चीजवस्तुओं पर जीएसटी स्लैब करने की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया हैं अर्जुन मोढवाडिया ने कहा कि यह बजट आम आदमी के लिए कटोरा दरखास्त के समान हैं कोरोना में मारे गए लोगों के परिवार को सहायता के लिए रु. 4 लाख के मुआवजे के ऐलान की अपेक्षा की जा रही है, वह भी आज के बजट में पूरी नहीं हुई वृद्धों के लिए आजीविका के साधन सामग्री ब्याजदर में भी कोई वृद्धि नहीं की गई राज्य सरकारों का सहायता के बजाए लोन देने का प्रावधान किया गया हैं बाजार में मांग पैदा करने या छोटे उद्योगों के विकास के लिए कोई प्रावधान बजट में नहीं हैं विदेशी यूनिवर्सिटी को न्यौता देकर देश में शिक्षा महंगी करने का प्रावधान किया गया हैं शहरी विकास के लिए उच्चस्तरीय समिति बनाकर देश के 50 प्रतिशत को शहरी क्षेत्र में शामिल कर गांवों को खत्म करने का प्रयास किया गया हैं मोढवाडिया ने कहा कि कुल मिलाकर आंकड़ों की मायाजाल रचकर फूल गुलाबी सपने दिखाए गए हैं, परंतु वास्तविकता में ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई कि जिससे महंगाई कम हो या बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले या गरीब, मध्यम वर्ग के लोगों को राहत मिले

आखिर में एनएएसए की टीम सफेद रेगिस्तान में रिसर्च करेगी

कच्छ, १ फरवरी ।

माता के मढ में मंगल ग्रह जैसी जमीन बाद अब सफेद रेगिस्तान में मंगल का कनेक्शन ढूंढने के लिए नासा कच्छ पहुंचा है।

नासा के वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर मिले सोल्ट क्रिस्टल बाद अब कच्छ के सफेद रेगिस्तान में देखने को मिलता क्रिस्टल के साथ तुलना करेंगे । फरवरी में एमिटी यूनिवर्सिटी, कच्छ यूनिवर्सिटी और नासा का संयुक्त प्रॉजेक्ट लागू होगा । जिसमें सोल्ट क्रिस्टल के डीएनए टेस्ट के बाद सुप्रसिद्ध सफेद रेगिस्तान और मंगल की जमीन के संबंध खुलेंगे । कच्छ के सफेद रेगिस्तान में चंद्र जैसा आभास बाद अब मंगल की एहसास होगा । मंगलग्रह और कच्छ के सफेद रेगिस्तान के सोल्ट क्रिस्टल के डीएनडी टेस्ट होगा । नासा की टीम को मंगल ग्रह का कच्छ के साथ का कनेक्शन मिल गया है । नासा की टीम कच्छ के रेगिस्तान में स्थित सफेद क्रिस्टल का मंगल ग्रह के साथ कनेक्शन ढूंढेगा । फरवरी में नासा की टीम कच्छ आयेगी और मंगल ग्रह पर मिलता हाइपर सेलाइन वोटर में होते बेक्टेरिया की जांच करेगी ।

प्रेम संबंध की आशंका में युवक को सच्चाई का सामना कराया

राजकोट, १ फरवरी ।

जेतपुर में अंधविश्वास का मामला सामने आया है । युवती के साथ प्रेम संबंध की आशंका में युवक को सच्चाई का सामना कराया । जिसमें गर्मा गर्म तेल में एक युवक को हाथ डलवाने का आरोप लग रहा है । जेतपुर के गिवीदरो क्षेत्र में माताजी के मढ में गर्म तेल में हाथ डलवाने की घटना की वजह से खलबली मच गई है । लोगों ने प्रेम संबंध की आशंका में चाकू की अपहरण करके युवक को तेल में हाथ डलवाया जाने की बात सामने आई है । फिलहाल युवक सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है । इस घटना की मिली जानकारी के अनुसार जेतपुर में अज्ञात शख्स ने अपनी पत्नी के साथ नाजायज संबंध की आशंका के आधार पर महिला सहित अन्य दो शख्सों के साथ मिलकर विक्रम भगवानजीभाई जादव नाम के युवक का अपहरण किया था । इसके बाद युवक को माताजी के मढ में ले गये थे । जहां अंधविश्वास का मामला हुआ । युवक को कहा गया कि यदि तेरा मेरी पत्नी के साथ संबंध नहीं हो तो गर्मा गर्म तेल की कड़ाही में हाथ डलवाया । लेकिन युवक ने ऐसा नहीं किया । बाद में तीन शख्सों ने युवक का हाथ पकड़कर कड़ाही में डलवाया था । इस घटना में युवक का हाथ जल गया था । इतना ही नहीं यह युवक पर तीनों शख्सों ने चाकू से हमला करने का प्रयास किया था । लेकिन युवक वहां से भाग गया था और सिविल अस्पताल पहुंच गया था । इस घटना के बाद पुलिस शिकायत दर्ज की गई है ।

अहमदाबाद मंडल पर फिर गूंजी छुक-छुक की आवाज व स्टीम इंजन की किलकारी

- अतीत की यादों को तरोताजा करता हुआ दिखा अद्भुत नजारा

अहमदाबाद (ईएमएस) पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल पर अहमदाबाद स्टेशन, साबरमती स्टेशन तथा डीआरएम ऑफिस में संरक्षित रखे गए हेरिटेज स्टीम लोकोमोटिव इंजन जो कभी भारतीय रेलवे की पटरी पर शासन करते थे। इन इंजनों का नवीनीकरण किया गया है, जिसमें आकर्षक कलर,वास्तविक संचालन की हूबहू स्मॉक एवं साउंड सिस्टम तथा मरम्मत कर स्थापित किया गया है। अहमदाबाद स्टेशन पर प्रदर्शित नैरोगेज हेरिटेज स्टीम लोको इंजन 587 जिसे ''अतीत गौरव'' के नाम से जाना जाता है, जो इंग्लैंड में . उ. बंगाल लिमिटेड कास्टल इंजीनियरिंग वर्क्स द्वारा 1937 में बनाया गया था। साबरमती स्टेशन पर प्रदर्शित मीटर गेज हेरिटेज स्टीम लोको 3430 भ्ङ है, जिसे ''शांतिदूत'' के नाम से जाना जाता है। जो 1963 में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी द्वारा निर्मित स्टैंडर्ड फ्रेट लोको है। जो 40 मील प्रति घंटे तक की रफ्तार से दौडा करता था। डीआरएम ऑफिस में प्रदर्शित नैरोगेज हेरिटेज स्टीम लोको 548 ॐ है जिसे ''प्रगति'' के नाम से जाना जाता है। जिसका निर्माण निप्पॉन शरयो सेजों कैशल कॉ. लिमिटेड जापान द्वारा 1957 में बनाया गया था। 73 वे गणतंत्र दिवस (26 जनवरी 2022) की पूर्व संध्या पर मंडल रेल प्रबंधक तरुण जैन की डिजायर एवं इनविजन के अनुसार वरिष्ठ मंडल मैकेनिकल इंजीनियर, अभिषेक कुमार सिंह के मार्गदर्शन में मेकेनिकल विभाग, मंडल दुर्घटना राहत ट्रेन कांकरिया के कर्मचारियों द्वारा इन संरक्षित हेरिटेज स्टीम इंजीनों का नवीनीकरण किया गया है। शाम 17:00 और 18:00 बजे प्रति/घंटे 2 मिनट के लिए स्मोक और साउंड सिस्टम को प्रोग्रामिंग किया गया है।

केंद्र सरकार का यह बजट आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने वाला लोकरंजक बजट है: मुख्यमंत्री

अहमदाबाद (ईएमएस) मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के वर्ष 2022-23 के आम बजट को 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को संपूर्ण रूप से साकार करने वाला बजट करार दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत करते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह सर्वसमावेशी, सर्वपोषक और लोकरंजक बजट है। मुख्यमंत्री ने बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के दौरान देश के नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन, जरूरतमंदों को मुफ्त राशन और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि जैसे स्वास्थ्य संबंधित अनेक उपायों का लाभ देने के बावजूद केंद्र सरकार ने जनता पर एक भी रुपए का अतिरिक्त कर बोझ डाले बिना यह बजट पेश किया है। कोरोना महामारी के प्रभाव से समूची अर्थव्यवस्था को तेजी से उबारने के लिए युवाओं, महिलाओं, किसान, विद्यार्थी, व्यवसायी और नियोक्ताओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ग्रामीणों सहित सभी के सर्वग्राही विकास और उत्थान की प्रतिबद्धता वाले इस बजट के लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के अमृत पर्व वर्ष का यह 'अमृत बजट' अगले 25 वर्ष के 'अमृत काल' पर अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने की नींव रखने वाला बजट है। इस बजट में भारत की आजादी के 75 से 100 साल पूरे होने तक की यात्रा का ब्लू प्रिंट और विकास का रोडमैप है। उन्होंने आगे कहा कि इस बजट में पीएम गति शक्ति, सर्वसमावेशक विकास, उत्पादकता वृद्धि और निवेश के अवसर जैसी चार प्राथमिकताओं पर विशेष जोर दिया गया है। इस बजट में पीएम गतिशक्ति प्रोजेक्ट के तहत देश एवं राज्य के विकास की गति को रफ्तार देने का ध्येय निहित है। उन्होंने कहा कि गुजरात 'पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट' को लागू करने के मामले में अग्रणी रहा है और अभी भी देश में सबसे आगे रहने को संकल्पबद्ध है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि स्थानीय व्यवसायों एवं आपूर्ति श्रृंखलाओं की सहायता के लिए 'वन स्टेशन, वन प्रोडक्ट' का दृष्टिकोण लोकप्रिय बनेगा। पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आगामी एक वर्ष में 80 लाख घरों का निर्माण होने से लोगों का खुद के घर का सपना साकार होगा। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना के तहत आगामी पांच वर्षों में 60 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार होने से आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना साकार होगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने के साथ ही 'पीएम ई-विद्या' योजना के अंतर्गत एक कक्षा-एक टीवी चैनल कार्यक्रम से सभी राज्यों के पहली से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं में प्रादेशिक भाषाओं में पूरक शिक्षा दी जा सकेगी। अभी सहकारी मंडलियों को 18.5 की दर से न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) का भुगतान करना पड़ता है, जिसे घटाकर 15 फीसदी किया गया है। इसी तरह, 1 से 10 करोड़ रुपए तक की आय वाली सहकारी समितियों पर लगने वाले अधिभार यानी सरचार्ज की मौजूदा 12 फीसदी की दर को घटाकर 7 फीसदी कर दिया गया है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं देश के पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह को हृदय से धन्यवाद दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फसल के मूल्यांकन और भूमि अभिलेखों के डिजिटाइजेशन में किसान ड्रोन के उपयोग की पहल को गुजरात में भी क्रियान्वित करेंगे। इस बजट में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का जो संकल्प किया गया है, उसे गुजरात में सफलतापूर्वक अमलीजामा पहनाने की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि बाजरा और ज्वार जैसे अनाजों के मूल्यवर्धन के लिए सहायता से राज्य के आदिवासी पट्टे के किसानों को फायदा होगा। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि अपनी 'ई-व्हीकल पॉलिसी' के साथ गुजरात की मंशा इस क्षेत्र में भी आगे रहने की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वास आधारित शासन , ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार सुगमता और ईज ऑफ लिविंग अर्थात जीवन जीने की सुगमता की संकल्पना को गुजरात ने साकार किया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में गुजरात की गिफ्ट सिटी (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी) के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। जिसके अंतर्गत वित्तीय प्रबंधन, फिनटेक, टेक्नोलॉजी और गणित आदि के लिए अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। गिफ्ट सिटी में एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र भी शुरू होगा। उन्होंने आगे कहा कि सूरत के जेम्स एंड ज्वेलरी उद्यमियों को राहत देने वाले इस बजट में पॉलिश हीरे और जेम्स स्टोन (रत्नों) पर लगने वाली कस्टम डयूटी को घटाकर 5 फीसदी किया गया है। इससे सूरत के जेम्स एंड ज्वेलरी उद्योग को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस तरह देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट सर्वसमावेशी और सर्वपोषक बजट है। मुख्यमंत्री ने ऐसे जनहितकारी एवं विकासोन्मुखी बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का गुजरात की जनता की ओर से आभार व्यक्त किया है।

विधानसभा अध्यक्षा ने नीमाबेन आचार्य स्वतंत्रता सैनानी अब्बास तैयबजी को पुष्पाजंलि दी

गांधीनगर (ईएमएस) गुजरात विधानसभा की अध्यक्षा डॉ. नीमाबेन आचार्य ने आज पोडियम स्थित स्वतंत्रता सैनानी अब्बास शमशुद्दीन तैयबजी के तैलचित्र पर पुष्पाजंलि अर्पण कर उनके योगदान को याद किया इस मौके पर डॉ. नीमाबेन आचार्य ने कहा कि गांधी जी के प्रिय, न्याय प्रेमी, धर्म प्रेमी और प्रामाणिक जीवन के प्रखर ऐसे तैयबजी के जीवन से प्रेरणा लेकर हम सभी प्रमाणिकता के प्रहरी बने उन्होंने कहा कि तैयबजी का जन्म 1 फरवरी 1854 को वडोदरा में हुआ था वडोदरा में शिक्षा प्राप्त कर लंदन जाकर बेरिस्टर बने और सयाजीराव गायकवाड सरकार में वे चीफ जस्टिस बने तैयबजी गांधी के एक वफादार व्यक्ति थे तिलक स्वराज फंड के लिए सबसे अधिक फंड एकत्र करने वाले वह पहले व्यक्ति थे इस मौके पर पशुपालन एवं गौसंवर्धन राज्यमंत्री देवा माला, गुजरात विधानसभा के दंडक रमेश कटारा, विधानसभा के सचिव डीएम पटेल और विधानसभा के अधिकारी और कर्मचारियों ने तैयबजी के तैलचित्र पर पुष्पाजंलि दी

काल बनकर दौड़ रही बस ने वृद्ध को रौंदा, गुस्साए लोगों ने वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी की

भरुच (ईएमएस) भरुच के शेरपुरा गांव के निकट तेज रफ्तार में दौड़ रही बस ने एक वृद्ध को रौंद दिया इस घटना में वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई घटना से गुस्साए आसपास के लोगों ने कई वाहनों में तोड़फोड़ की और दो बसों में आग लगा दी घटनास्थल पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम ने हालात पर काबू पाया जानकारी के मुताबिक भरुच शहर के निकट शेरपुरा निवासी करीब 65 वर्षीय इस्माइल आदमभाई मांचवाला सोमवार की देर रात यात्रियों को उतारने के बाद शेरपुरा स्टेन्ड के निकट बस को खड़ी कर नीचे उतर रहे थे उस वक्त दहेज की ओर से आ रही दूसरी बस ने इस्माइल मांचवाला को अपनी चपेट में ले लिया इस हादसे में सिर और शरीर में कई जगह गंभीर चोट लगने से वृद्ध की घटनास्थल पर ही मौत हो गई घटना से गुस्साए आसपास के लोगों में आक्रोश भड़क उठा और दुर्घटना को अंजाम देकर भाग रहे बस को रोक लिया गुस्साए लोगों ने बस में तोड़फोड़ शुरू कर दी और उसमें आग लगा दी इतना ही नहीं वहां से गुजर रहे अन्य वाहनों में भी तोड़फोड़ और आगजनी की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई और गुस्साए लोगों को तितर बितर कर हालात पर काबू पाया हांलाकि तब तक आग बस में जलकर एक ढांचे में तब्दील हो चुकी थी पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज आगे की कार्रवाई शुरू की

श्री अनिल कुमार लाहोटी ने पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण किया

मध्य रेल के महाप्रबंधक श्री अनिल कुमार लाहोटी ने मंगलवार, 1 फरवरी, 2022 को पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

श्री लाहोटी ने आईआईटी रुड़की (पूर्व रुड़की विश्वविद्यालय) से मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग (स्ट्रक्चर) की डिग्री प्राप्त की है। वे भारतीय रेलवे सेवा इंजीनियर **(IRSE)** के 1984 बैच के वरिष्ठ अधिकारी हैं। श्री अनिल कुमार लाहोटी को रेलवे में विविध पदों पर कार्य करने का गहन अनुभव प्राप्त है। इन्होंने मध्य रेल से अपनी रेल सेवा शुरु की और नागपुर, जबलपुर (अब पश्चिम मध्य रेलवे पर) और भुसावल मंडल और मध्य रेल मुख्यालय में 1988 से 2001 तक विभिन्न पदों पर काम किया है। इन्होंने सदस्य इंजीनियरिंग, रेलवे बोर्ड के विशेष कार्यकारी अधिकारी, मुख्य इंजीनियर (निर्माण), उत्तर रेलवे, कार्यकारी निदेशक (ट्रैक मशीन), रेलवे बोर्ड और उत्तर मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य इंजीनियर के रूप में भी काम किया है। मध्य रेल के महाप्रबंधक का कार्यभार संभालने से पूर्व श्री लाहोटी उत्तर रेलवे में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) के पद पर कार्यरत थे।

आपने नई दिल्ली स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित करने की योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें भूमि और एअर स्पेस का वाणिज्यिक विकास और सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल का विकास शामिल है। आपने दिल्ली में भीड़भाड़ कम करने के लिए आनंद विहार में दिल्ली में एक नए दिशात्मक टर्मिनल तथा नई दिल्ली स्टेशन के महत्वपूर्ण द्वितीय प्रवेशद्वार की योजना बनाई और निर्माण किया। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण), मुख्य इंजीनियर (निर्माण) के पदों पर कार्य करते हुए आपने नई रेल लाइनों, दोहरीकरण, यार्ड रिमॉडलिंग औ- महत्वपूर्ण पुलों के निर्माण जैसी ढांचागत परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया।

श्री अनिल कुमार लाहोटी, रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक सिविल इंजीनियरिंग (योजना) के रूप में संरक्षा, रखरखाव, पुनर्वास और स्थायी मार्ग के उन्नयन, उच्च एक्सल भार और ट्रैक पर उच्च गति के संचालन पर नीति तैयार करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं।

उत्तर मध्य एवं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण कुछ ट्रेनें निरस्त

उत्तर मध्य रेलवे में यार्ड रीमॉडलिंग के लिए प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर तथा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में तीसरी लाइन को चालू करने के लिए रूपौंड स्टेशन पर नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के कारण कुछ ट्रेनें निरस्त रहेंगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री सुमित ठाकुर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इन ट्रेनों का विवरण इस प्रकार हैः-निरस्त ट्रेनेंः

1. 7, 14 एवं 21 फरवरी, 2022 को छूटने वाली ट्रेन संख्या 09065 सूरत-छपरा स्पेशल
2. 9, 16 एवं 22 फरवरी, 2022 को छूटने वाली ट्रेन नंबर 09066 छपरा-सूरत स्पेशल
3. 3 फरवरी, 2022 को छूटने वाली ट्रेन संख्या 22909 वलसाड-पुरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस
4. 6 फरवरी, 2022 को छूटने वाली ट्रेन संख्या 22910 पुरी-वलसाड सुपरफास्ट एक्सप्रेस
5. 23 फरवरी, 2022 को छूटने वाली ट्रेन संख्या 09447 अहमदाबाद-पटना सुपरफास्ट स्पेशल
6. 25 फरवरी, 2022 को छूटने वाली ट्रेन संख्या 09448 पटना-अहमदाबाद सुपरफास्ट स्पेशल
7. 5 फरवरी, 2022 को छूटने वाली ट्रेन संख्या 20971 उदयपुर सिटी-शालीमार एक्सप्रेस
8. 6 फरवरी, 2022 को छूटने वाली ट्रेन संख्या 20972 शालीमार-उदयपुर सिटी एक्सप्रेस

मालिक-मुद्रक- प्रकाशक व संपादक: लक्ष्मीचंद जी. अग्रवाल द्वारा, ब्रिजाशा ऑफसेट, जी.एम. कम्पाउन्ड, सरसपुर, अहमदाबाद -380018 में मुद्रित करवा कर वहीं से प्रकाशित किया। प्रातः कालीन E-mail : janhitaishi@yahoo.co.in फोन: 079-22921482 Mob.9375504122 , 9327086467 R.N.I. 63177/95